



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2011/आषाढ़ 9, 1933

No. 138]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2011/ASADHA 9, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

अंतिम जांच परिणाम

विषय : थाइलैंड, चीनी ताइपेई तथा नार्वे के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कॉस्टिक सोडा के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच का अंतिम जांच परिणाम ।

सं. 14/1/2010-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियमावली (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत थाइलैंड, नार्वे तथा ताइवान (चीनी ताइपेई) (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित कास्टिक सोडा के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए एम ए आई) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ ।
- आवेदन की प्रारंभिक जांच से कुछेक कमियों का पता चला जिन्हें आवेदक ने बाद में सुधार दिया था । अतः आवेदन विधिवत प्रलेखित माना गया था ।
- जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जांच शुरू करने का निर्णय लिया ।

- iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व पाटन के आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- v. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए प्राधिकारी ने 8 जून, 2010 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।
- vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार सार्वजनिक सूचना की प्रति समस्त ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्योरे आवेदक ने उपलब्ध कराए थे) को भेजी और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- vii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के समस्त ज्ञात आयातकों को भी सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी।
- viii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति उपलब्ध कराई। अनुरोध करने पर आवेदन की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने हेतु प्रश्नावलियां भेजीं:

चैमेक्स इंडस्ट्री कं. लि.
 फोनिक्स पल्प एंड पेपर कंपनी
 सियाम ओसीडेंटल इलेक्ट्रोकेमिकल कंपनी
 थाई फ्रेमेशन इंडस्ट्रीज
 थाई ऑर्गेनिक कैमिकल्स कं.
 थाई पेपर मिल्स
 थाई प्लास्टिक एंड कैमिकल्स पब्लिक कं. लि.
 थान्स्को कैमिकल कं. लि.
 कैथे कैमिकल्स कं. लि., 12 एफएल कुआंग
 बोरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि.

- x. संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों/एसोसिएशनों/दूतावास ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है:

फार्मोसा प्लास्टिक्स कार्पोरेशन, ताईवान
 विन्थाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड, विदेश व्यापार विभाग, थाइलैंड
 ट्राईकोन एनर्जी लिमिटेड, अमरीका

बोरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि., नॉर्वे
एल्कैम ए एस

- xi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

अभय कैमिकल लिमिटेड
अल्ब्राइट विल्सन कैमिकल्स लिमिटेड
अरविन्द मिल्स लिमिटेड
सैंट्रल पल मिल्स लिमिटेड
दीपक नाइट्राइट लिमिटेड
गोदरेज सोप्स लिमिटेड
गुजरात नर्मदा फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड
गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड
इंडियन फॉर्मर फर्टीलाइजर्स एंड कं. ऑप. लिमिटेड
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
जयस्यानात डाईकैम लिमिटेड
मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
नर्मदा कैमटूर पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
निरमा लिमिटेड
पब कैमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड
रामा न्यूज प्रिन्ट्स एंड पेपर लिमिटेड
रबमिन लिमिटेड
सबेरो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
टोरेंट गुजरात बायोटेक लिमिटेड
ट्रांसपैक सिलोक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
नेशनल एल्युमिनियम कं. लिमिटेड
साइनाइडीज एंड कैमिकल्स कंपनी
हिटसू इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अदनी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
लिबरा फोम्स
श्री रामचन्द्र स्ट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
बिलग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
डरूला ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
सी जे शाह एंड कं.
हरीश कुमार एंड कं.
हिंदुस्तान लिंक एंड रेजिन
हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड

- xii. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं और एसोसिएशन प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है :

दि डाईस्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई
 एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 वेदान्त एल्युमिनियम लिमिटेड

- xiii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।
- xiv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- xv. आवेदक कंपनियों से सूचना मांगी गई थी। क्षति से संबंधित सूचना दो और घरेलू उत्पादकों अर्थात् डी सी डब्ल्यू लि. तथा सोलारिस कं. ने प्रदान की थी। तथापि, मौखिक सुनवाई के समय उपस्थित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत के बाद और घरेलू उत्पादकों से सूचना जुटाने पर आपत्ति व्यक्त की थी तथा यह मांग की गई थी कि प्राधिकारी को क्षति निर्धारण हेतु उनकी सूचना पर विचार नहीं करना चाहिए। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने डी सी डब्ल्यू लि. तथा सोलारिस लि. द्वारा जांच शुरुआत के बाद दायर सूचना पर विचार न करने का निर्णय लिया और इसके बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।
- xvi. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. यह जांच 1 अक्टूबर, 2008 से 31 दिसंबर, 2009 की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2006- मार्च, 07, अप्रैल, 2007-मार्च, 08, अप्रैल, 2008-मार्च, 09 की अवधि और जांच अवधि शामिल थी।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई करने के लिए प्राधिकारी ने 24 मई, 2011 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से लिखित

अनुरोध और उत्तर यदि कोई हो दायर करने की सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और उत्तरों पर अंतिम जांच परिणाम में संगत सीमा तक विचार किया गया है।

- xix. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन 17 जून, 2011 को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- xx. *** चिन्ह इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने उसे पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत गोपनीय ही माना है।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू समान वस्तु

ख.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

3. घरेलू उद्योग के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

- i. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद कास्टिक सोडा है:
- ii. कास्टिक सोडा के समस्त रूप (तरल एवं ठोस) विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।
- iii. कास्टिक सोडा के ये दोनों रूप समान वस्तुएं हैं। प्राधिकारी द्वारा पूर्व में की गई विभिन्न जांचों में इस मुद्दे की जांच की गई है। इस मुद्दे की सेस्टेट ने भी जांच की है और यह माना है कि कास्टिक सोडा के ये रूप समान वस्तुएं हैं।

ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. तरल और फ्लैक रूप में कास्टिक सोडा कीमत के संबंध में काफी भिन्न है। अतः तरल रूप और फ्लैक रूप के लिए पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध का अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

5. प्राधिकारी ने इस मामले की निम्नानुसार जांच की है:

- i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कास्टिक सोडा तरल और कास्टिक सोडा फ्लैक कास्टिक सोडा के केवल दो अलग-अलग रूप हैं। पूर्ववर्ती रूप का आगे प्रसंस्करण कर ठोस रूप प्राप्त किया जाता है। ये दोनों तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग के रूप में

अनिवार्यतः समान हैं । उत्पाद के स्वरूप में मात्र अंतर होने से वह असमान वस्तु नहीं बन जाती है । पूर्ववर्ती सभी जांचों में प्राधिकारी ने कास्टिक सोडा के तरल और ठोस रूप को एक ही उत्पाद माना है ।

- ii. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे आम तौर पर कास्टिक सोडा कहा जाता है । कास्टिक सोडा को रासायनिक रूप से NaOH के रूप में जाना जाता है । कास्टिक सोडा झागदार, तीखा अल्कलाइन गंधहीन द्रव है जिसका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कच्ची सामग्री या सहायक सामग्री के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है । कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों-तरल एवं ठोस में किया जाता है । ठोस फ्लैक, प्रिल, दानेदार अथवा किसी अन्य रूप में हो सकता है । कास्टिक सोडा के सभी रूप इस जांच की विषय वस्तु हैं ।
- iii. कास्टिक सोडा का उपयोग लुग्दी तथा कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न तथा स्टेपल फाइबर, एल्युमिनियम, काटन, वस्त्र, टॉयलेट एवं वस्त्र धुलाई साबुन, डिटरजेंट, रंजक पदार्थों, औषधियों तथा भेषजों, वनस्पति पेट्रोलियम शोधन आदि के विनिर्माण में किया जाता है ।
- iv. कास्टिक सोडा अकार्बनिक रसायन है और यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष सं. 2815 के अंतर्गत श्रेणीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।
- v. कास्टिक सोडा का उत्पादन तीन प्रक्रियाओं, डायफाग्राम, मरकरी और मेम्ब्रेन के जरिए किया जाता है । तथापि, प्रत्येक प्रक्रिया से उत्पादित अंतिम उत्पाद में समान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं होती हैं ।
- vi. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार उपबंध है:

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

- vii. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक के उत्पादों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य तथा उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन और वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है ।

- viii. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है । यद्यपि, उत्पाद का उत्पादन अलग-अलग प्रक्रियाओं के जरिए किया जाता है, तथापि, भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य तथा उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन और संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के संबंध में तुलनीय है । ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता इन दोनों का अदल-बदल कर उपयोग कर रहे हैं । किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है । याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र तथा आधार

ग.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

6. घरेलू उद्योग के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

- i. यह याचिका अल्कली मैनु. एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की है ।
- ii. एसोसिएशन ने कार्यकारी समिति की बैठक में पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु वर्तमान याचिका दायर करने का निर्णय लिया । यह निर्णय एसोसिएशन के कानून के अनुसार लिया गया है ।
- iii. कार्टिक सोडा के अखिल भारतीय उत्पाद एसोसिएशन के सदस्य हैं ।
- iv भागीदार कंपनियों और समर्थनकर्ता कंपनियों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है । अतः याचिका में आधार की पूर्ति होती है और याचिकाकर्ता नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

ग.2 हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

7. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:- :

- i. याचिकाकर्ता जांच में भाग लेने के लिए एसोसिएशनों के सदस्यों को सुविधानुसार शामिल कर रहा है और बाहर रख रहा है ।
- ii. चुनिन्दा भागीदारी और घरेलू उद्योग की संरचना से स्पष्टतः पारदर्शिता के अभाव तथा समग्र प्रभावित उद्योग की सही स्थिति को विकृत करने का पता चलता है ।
- iii. याचिकाकर्ता को केवल निजी व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए बार-बार और लगातार आवेदन दायर करने की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

i. "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।

ii. यह आवेदन अल्कली मैन्यु. एसो. ऑफ इंडिया (ए एम ए आई) ने दायर की थी । यह आवेदन निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने संगत सूचना प्रदान की थी, की ओर से एसोसिएशन ने दायर की थी ।

गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
डी सी एम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड
एस आई ई एल
बिहार कॉस्टिक एंड कैमिकल्स लिमिटेड

iii. निम्नलिखित कंपनियों ने ए एम ए आई द्वारा दायर याचिका का समर्थन किया ।

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड
सोलजीज कैमटैक लिमिटेड
डी सी डब्ल्यू लिमिटेड
जयश्री कैमिकल लिमिटेड

iv. जांच शुरुआत के बाद सोलारिसकैमटैक लि. और डी सी डब्ल्यू लि. ने भी क्षति सूचना प्रदान की । तथापि, मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरुआत के बाद उक्त दोनों घरेलू उत्पादकों द्वारा सूचना जोड़ने पर आपत्ति व्यक्त की और प्राधिकारी से क्षति निर्धारण हेतु उनकी सूचना पर विचार न करने का अनुरोध किया । विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने डी सी डब्ल्यू लि. और सोलारिस लि. द्वारा दायर सूचना पर विचार न करने का निर्णय लिया और इसके बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया ।

- v. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध उत्पाद से संबंधित प्रत्येक मामले में घरेलू उद्योग की संरचना बदली है । इस संबंध में प्राधिकारी ने यह पाया है कि यह अपेक्षा करने के लिए कानून में कुछ भी निर्धारित नहीं है कि एक ही उत्पाद से संबंधित अलग-अलग जांचों में घरेलू उद्योग की संरचना एक समान रहेगी । न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध किया है कि इससे वर्तमान जांच के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह हुआ है ।
- vi. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन कंपनियों ने क्षति संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं और जिन्हें प्राधिकारी ने विधिवत रिकॉर्ड में लिया है, उनका सामूहिक उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख भाग (लगभग 44 प्रतिशत) बनता है । अतः याचिका में नियमों के अंतर्गत आधार संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति होती है । इसके अलावा, भागीदार कंपनियां नियमों के अर्थ के भीतर “घरेलू उद्योग” हैं ।

घ. अन्य मुद्दे

घ 1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

9. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में से कुछ मुद्दे निम्नानुसार हैं:

- (क) अल्कली मेन्यु एसो. ऑफ इंडिया के पत्र में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए संबद्ध देश के रूप में केवल थाइलैंड का उल्लेख है । अतः अन्य देशों के खिलाफ जांच अनुचित है ।
- (ख) रक्षोपाय महानिदेशक, के जांच परिणाम पर डी जी ए डी द्वारा विचार अपेक्षित है ।
- (ग) जुलाई, 2009 के बाद भारी सुधार हुआ है ।
- (घ) महानिदेशक (रक्षोपाय) ने मार्च, 2010 तक के आंकड़ों पर विचार किया और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सूचना और बाद में हुए घटनाक्रम पर विचार करना चाहिए ।
- (ङ.) क्षति विश्लेषण : वर्ष 08-09 की ति. 3 में लाभप्रदता में गिरावट वैश्विक मंदी के कारण आई थी ।
- (च) जांच अवधि अनुचित है क्योंकि उसमें विश्व बाजार में मंदी शामिल है ।
- (छ) याचिकाकर्ता ने आयात सौदों को दोहरा कर आयात मात्रा को अधिक बताया है । याचिका में ऐसी सूचना निहित है जो 853.85 प्रतिशत तक अधिक बताई गई है ।
- (ज) कारखाना निर्यात कीमत निकालते समय याचिकाकर्ता ने उन कटौतियों का दावा किया है जिनके बारे में याचिकाकर्ता ने याचिका में कोई साक्ष्य नहीं दिया है ।

- (झ) याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है । यहां तक कि समग्र घरेलू उद्योग से संबंधित संचयी आंकड़ों को भी गोपनीय होने का दावा किया गया है ।
- (ट) वर्तमान जांच शुरुआत श्रृंखलाबद्ध जांच के बारे में 14 नवंबर, 2001 की मंत्रीस्तरीय घोषणा के विरुद्ध है । वर्तमान जांच की शुरुआत हेतु आवेदन 5 मई, 2011 को दायर किया गया था । वर्तमान आवेदन उसी अवधि के दौरान ताइवान से हुए आयातों के बारे में अंतिम नकारात्मक निर्धारण के 365 दिन के भीतर दायर किया गया है ।
- (ठ) मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित पुस्तिकाओं के अनुसार कनाडा से हुए आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं । अतः कनाडा को जांच से अलग रखना उचित नहीं है ।

घ.2 याचिकाकर्ता के अनुरोध:

10. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (क) याचिकाकर्ता ने इस संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया था । लिखित अनुरोधों में किए गए उल्लेख के अनुसार याचिका में दिए गए संगत भाग के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिका थाइलैंड, नार्वे और ताइवान के बारे में है ।
- (ख) रक्षोपाय महानिदेशक ने जो बताया है वह यह है कि खासकर, पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण रक्षोपाय शुल्क को निरंतर लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है । महानिदेशक ने यह उल्लेख नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को आगे कोई क्षति नहीं हुई है और पाटनरोधी शुल्क को लागू करना अपेक्षित नहीं है ।
- (ग) महानिदेशक के अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा किया जाता है जिसमें इस बात की स्पष्ट पुष्टि की गई है कि महानिदेशक ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करना अपेक्षित नहीं है ।
- (घ) यह तर्क तथ्यतः गलत है क्योंकि इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि ति. 3 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम रही है । वस्तुतः ति.3 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच अवधि के परवर्ती भाग की तुलना में बेहतर रही थी, निम्नलिखित तालिका से प्रदर्शित होता है ।

क्र. सं.	माह/ तिमाही	एन एस आर लाई	एन एस आर लाई	एन एस आर फ्लेक	एन एस आर फ्लेक	एन एस आर क्लोरीन	एन एस आर क्लोरीन	एन एस आर ईसीयू	एन एस आर ईसीयू	एन एस आर ईसीयू	एन एस आर ईसीयू
		रू./मी.ट.	सूचीबद्ध	रू./मी.ट.	सूचीबद्ध	रू./मी.ट.	सूचीबद्ध	रू./मी.ट.	सूचीबद्ध	अम.डॉ./ मी.ट.	सूचीबद्ध
1	2006-07	***	100	***	100	***	100	***	100	***	100

2428 G2/11-2B

2	2007-08	***	94	***	97	***	116	***	97	***	109
3	2008-09	***	118	***	122	***	64	***	109	***	109
4	अक्टू '08- दिस. '09 (जांच अवधि)	***	112	***	109	***	29	***	99	***	92
5	अक्टू '08- दिस. '09	***	121	***	118	***	6	***	102	***	94
6	जन. '09- मार्च, '09	***	131	***	139	***	Neg.	***	106	***	98
7	अप्रैल '09- जून '09	***	122	***	120	***	6	***	103	***	94
8	जुलाई '09- सित. '09	***	95	***	90	***	119	***	99	***	92
9	अक्टू '09- दिस. '09	***	93	***	88	***	28	***	82	***	79

- (ड.) यह तर्क विधितः और तथ्यतः अस्वीकार्य है । अपने खुद के कथनानुसार यह समस्या “वैश्विक मंदी” की थी । वर्तमान में हम “वैश्विक मंदी” से सरोकार नहीं रखते हैं । यह भारत विशिष्ट मंदी की समस्या नहीं थी । इसके अलावा, यद्यपि, विश्व बाजार किस अवधि में प्रभावित हुआ तथापि, भारतीय बाजार मंदी से प्रभावित नहीं हुआ । अतः जहां तक भारतीय उत्पादकों का संबंध है, उनके निष्पादन पर तथाकथित मंदी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था ।
- (घ.) इस मुद्दे को पूर्ववर्ती जांचों में स्पष्ट किया जा चुका है । संशोधित आयात विवरण दायर किया जा चुका है । संक्षेप में आई बी आई एस के आयात आंकड़ों में ही बार-बार आयात सौदे दर्शाए गए थे जिन पर याचिकाकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत करते समय भरोसा किया था ।
- (छ.) याचिकाकर्ता ने अत्यधिक रूढ़िवादी अनुमान अपनाए हैं- । इस संबंध में वास्तविक सूचना संबंधित पक्षकारों के पास है । याचिकाकर्ता संगत साक्ष्य भी प्रदान नहीं कर सका क्योंकि याचिकाकर्ता संगत सूचना का प्रतिनिधि नहीं है ।
- (ज.) याचिकाकर्ता ने ऐसी सूचना प्रकट की है जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील नहीं है । ऐसी सूचना जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील है अथवा जिसके प्रकटन से सदस्य कंपनियों के व्यापारिक हितों पर भारी प्रभाव पड़ता है, का प्रकटन नहीं किया जा सकता ।
- (झ.) ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । वर्तमान जांच शुरुआत प्राधिकारी के पूर्ववर्ती जांच परिणाम के 12 माह बाद की गई है ।
- (ट.) यह तर्क निराधार है । लिखित अनुरोधों पर भरोसा किया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि पश्चिमी क्षेत्र में भारी मात्रा में आयात हुए हैं । वस्तुतः पूर्वी शी. शु. पत्तनों पर नगण्य आयात हुए हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि एल्युमिनियम उद्योगों की खपत कौस्टिक सोडा की कुल खपत की मात्रा *** % बनती है । संगत सूचना नीचे पुनः प्रस्तुत है

क्र. सं.	अंतिम प्रयोक्ता	खपत %
1	पल्प तथा पेपर	20.25
2	एल्युमिना	17.92
3	ऑर्गेनिक्स	10.21
4	इनोरोगेनिक	11.32
5	सोप्स एंड डिटरजेंट्स	7.43
6	टेक्सटाइल्स	20.33
7	वाटर ट्रीटमेंट	1.78
8	विविध	10.70

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच:

- क. महानिदेशक, रक्षोपाय के जांच परिणामों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि महानिदेशक, रक्षोपाय के जांच परिणाम आयात में वृद्धि से संबंधित हैं जो उस आधार से अलग हैं जिस पर पाटनरोध हेतु विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उपाय की सिफारिश की जाती है ।
- ख. महानिदेशक, रक्षोपाय के दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के जांच परिणामों के भाग 364 में उपलब्ध घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन आंकड़ों की तुलना डी जी ए डी को प्रस्तुत आंकड़ों से की गई है और यह पाया गया है कि दोनों आंकड़ों में तीन वर्ष समान हैं अर्थात् वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 । प्राधिकारी ने इन तीन वर्षों के दौरान उत्पादन आंकड़ों में थोड़ा अंतर पाया है जो कि लगभग ***% से ***% तक है । यह अंतर इस तथ्य के कारण हो सकता है कि महानिदेशक, रक्षोपाय की जांच में विचाराधीन उत्पाद कार्टिक सोडा लाई या जबकि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद लाई और फ्लैक्स दोनों हैं ।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई बढ़ी हुई आयात मात्रा के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने आंकड़ा एजेंसी जिससे उन्होंने आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त किए थे, की ओर से आयात सौदों के दोहराव के कारण हुई त्रुटि को स्वीकार किया है ।
- घ. ऊपर किए गए उल्लेखानुसार जांच अवधि के दौरान कनाडा से आयात मात्रा आई बी आई एस द्वारा सूचित जांच अवधि के दौरान कुल आयात मात्रा की तुलना न्यूनतम से कम पाई गई है जबकि आई बी आई एस ने डी जी सी आई एंड एस की तुलना में कुल आयात की मात्रा अधिक बताई है । प्राधिकारी ने दोनों स्रोतों से सौदे-वार आंकड़े उपलब्ध होने पर आई बी आई स्रोत जिसने डी जी सी आई एंड एस की तुलना में कुल आयात की मात्रा अधिक बताई है को स्वीकार किया है ।

घ.4 हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन पश्चात टिप्पणियां:

11. प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. वेदान्त एल्युमिनियम लिमिटेड तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-
 - (क) प्रकटन के अनुसार वेदान्त एल्युमिनियम लि. को हितबद्ध पक्षकारों में शामिल नहीं किया गया है ।
 - (ख) कार्बोनाट सोडा लाई और फ्लैक्स दो अलग-अलग उत्पाद हैं और अलग-अलग गुणधर्मों, प्रयोगों एवं कीमत के कारण वे समान वस्तुएं नहीं हैं ।
 - (ग) क्लोरीन एवं कार्बोनाट सोडा को विश्व भर में सह-उत्पाद माना जाता है । भारत में भी उन्हें सह-उत्पाद माना जाना चाहिए ताकि अलग-अलग परिकलित उनकी उत्पाद लागत तिरा विलगन बिन्दु तक उनकी साझा लागत को समान रूप से विभाजित किया जा सके ।
 - (घ) आम तौर पर घरेलू विनिर्माता क्लोरीन का निपटान नहीं कर सकते हैं और इस कारण से पूरी क्षमता के साथ प्रचालन नहीं कर सकते ।
 - (ङ) कार्बोनाट सोडा के उत्पादन का हिसाब-किताब क्लोरीन के हिसाब-किताब से जुड़ा हुआ है । अतः दोनों उत्पादों के लिए आय एवं लागत का परिकलन संयुक्त आधार पर किया जाता है ।
 - (च) दो वित्त वर्षों के भागों को शामिल करते हुए जांच अवधि का चयन किया गया है ताकि घरेलू उद्योग आंकड़ों में हेरफेर न कर सके ।
 - (छ) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और वस्तुतः उन्हें भारी लाभ और निवेश पर आय हो रही है । उन कंपनियों का संदर्भ उद्धृत किया गया है जिन्होंने लगाई गई पूंजी पर उच्च आय दर्ज की है ।
 - (ज) आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है । वस्तुतः भारत में वस्तु की कमी के कारण आयात हुए हैं । निम्निखित कारणों से भारत में कार्बोनाट सोडा के आयात की आवश्यकता है :-
 - i. क्लोरीन के निपटान के मुद्दे के कारण घरेलू उद्योग की प्रभावी सीमित क्षमता ।
 - ii. मांग एवं आपूर्ति में भौगोलिक असंतुलन ।
 - (झ) भारत में घरेलू उद्योग को क्षति का वास्तविक कारण विद्युत की उच्च लागत है न कि पाटित आयात ।

- (ट) क्षतिरहित कीमत के परिकलन के लिए आर जे एल बंगाम निर्दिष्ट प्राधिकारी-2006 (202) ई एल टी 23 (एस सी) मामले के अनुसार विद्युत की बाजार कीमत की जानी होती है । कास्टिक सोडा के लागत निर्धारण के लिए क्लोरीन को सह-उत्पाद माना जाना चाहिए ।
- (ठ) प्राधिकारी द्वारा कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों के उत्पादन के अनुपात का उल्लेख किया जाना चाहिए । वर्तमान जांच में कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 50% से कम है । अतः वर्तमान जांच के लिए वे पात्र नहीं हैं ।
- (ड) प्राधिकारी ने एक स्थान पर नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने कीमत में कमी की है और दूसरे स्थान पर नोट किया है कि कीमत में बिक्री की लागत में हुई वृद्धि से कम थी ।
- (ढ) प्रकटन विवरण तक आयात आंकड़ों में लगातार परिवर्तन किए गए हैं ।
- (ण) जांच से कनाडा को बाहर रखने से जांच शुरूआत कानूनी रूप से संदिग्ध हो जाती है ।
- (त) निर्यातक ने स्वतंत्र रूप से आई बी आई एस आंकड़े प्राप्त किए हैं और यह नोट किया गया है कि कनाडा के आंकड़े अभी भी न्यूनतम से अधिक हैं तथा कनाडा की कीमतें ताइवान से आयात की तुलना में कम हैं ।
- (थ) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों को अंगीकार करने एवं उनके संग्रहण की पद्धति का विशिष्ट रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए और विचार की गई सौदा प्रविष्टियों को उनकी मात्रा एवं कीमतों सहित सूचित करना चाहिए ।
- (द) कार्यान्वयन मुद्दों के संबंध में नवंबर, 2001 में दोहा में चौथे सत्र में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह सहमति हुई थी कि पूर्ववर्ती नकारात्मक जांच परिणाम के 365 दिनों के भीतर कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी । ई यू, इंडोनेशिया तथा चीनी ताइपेई से कास्टिक सोडा के संबंध में निर्णायक समीक्षा में ताइवान के संबंध में जांच परिणाम नकारात्मक रहे थे । वर्तमान आवेदन उक्त नकारात्मक जांच परिणाम के 365 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया है ।
- (ध) निर्दिष्ट प्राधिकारी यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि वर्तमान संबद्ध देशों से कितनी क्षति हुई है और समानान्तर जांचों में दूसरे देशों से कितनी क्षति हो रही है । घरेलू उद्योग को हुई क्षति समानान्तर जांचों में दूसरे देशों के कारण है ।
- (न) पाटन मार्जिन के निर्धारणार्थ लाई एवं फ्लैक्स पर संयुक्त रूप से विचार किया गया था जो उपयुक्त नहीं है ।

(प) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षति रहित कीमत से अधिक है ।

घ.5 रॉयल नार्वेजियन दूतावास के प्रकटन पश्चात अभ्यावेदन:

12. रॉयल नार्वेजियन दूतावास के अभ्यावेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. नार्वेजियन कं. एल्केम ए एस ने भी उत्तर दिया है परंतु प्रकटन विवरण में उसका उल्लेख नहीं है ।
- ii. अनुबंध-1 पैरा-4 में गलत उल्लेख है कि विचाराधीन उत्पाद पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है । नॉर्वे ने उल्लेख किया है कि "जांच में कास्टिक सोडा के दो भिन्न-भिन्न रूपों को शामिल किया गया है । ठोस व्यापार एच एस कोड 2815.11 के अंतर्गत किया जाता है और लाई का 2815.12" के अंतर्गत ।
- iii. बोरेगार्ड के संबंध में यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त नहीं है कि "जांच अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भारत को कोई निर्यात नहीं किया है" और "प्राधिकारी" कंपनी के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित नहीं समझते हैं" । यह पाटनरोधी करार के प्रतिकूल है ।
- iv. कंपनी को प्राधिकरण से कोई अपर्याप्तता टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है ।
- v. दोनों कंपनियों द्वारा भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया है और इसलिए उनके विरुद्ध कोई पाटनरोधी जांच नहीं की जानी चाहिए ।
- vi. नार्वे द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारणीय आधार के रूप में क्लोर अल्कली से कीमत सूचना पर सवाल उठाया गया है । दी गई कीमत सूचना में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि प्राधिकारी द्वारा परिकलन के लिए कौन सी कीमतों का उपयोग किया गया है ।
- vii. शिकायतकर्ता ने नार्वे से ठोस रूप में कास्टिक सोडा का कोई आयात नहीं दर्शाया है । अधिकारिक नार्वेजियन निर्यात सांख्यिकी से इसकी पुष्टि की गई है । अतः ठोस रूप में कास्टिक सोडा के लिए पाटन या क्षति अथवा कारणात्मक संबंध तथा तत्पश्चात लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क का दावा करने का कोई आधार नहीं है ।
- viii. दोनों कंपनियों ने अपने उत्तर में दर्शाया है कि उनके द्वारा भारतीय बाजार में पाटन अथवा निर्यात भी नहीं किया जा रहा है ।

घ.6: याचिकाकर्ता की प्रकटन पश्चात टिप्पणियां:-

13. याचिकाकर्ता की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

- i. केवल नियत राशि आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।
- ii. क्षति रहित कीमत (एन आई डी) के निर्धारणार्थ बाजार मूल्यों पर आबद्ध निविष्टियों का मूल्यांकन ।

- iii. प्राधिकारी द्वारा एन आई पी के निर्धारणार्थ सकल अचल परिसंपत्तियों पर या वैकल्पिक रूप से निवल अचल परिसंपत्तियों पर उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर विचार किया जाए ।
- iv. चूंकि विदेशी उत्पादक सहयोग नहीं कर रहे हैं अतः प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के साथ कार्यवाही करनी चाहिए ।

घ.7 प्राधिकारी द्वारा जांच:

14. प्राधिकारी ने निम्नानुसार हितवद्ध पक्षकारों के प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है:-

- (क) वर्तमान जांच में वेदान्त अल्युमिनियम लि. के अभ्यावेदनों की विधिवत जांच की गई है ।
- (ख) प्राधिकारी नोट करते हैं कि कास्टिक सोडा लाई और कास्टिक सोडा फ्लैक्स सोडा के दो अलग-अलग रूप हैं । ठोस रूप प्राप्त करने के लिए लाई का और प्रसंस्करण किया जाता है । तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और उपयोग के रूप में दोनों एक ही हैं । केवल उत्पाद के रूप में अंतर से दोनों असमान उत्पाद नहीं हो जाते हैं । सभी पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने कास्टिक सोडा के लाई और ठोस रूप को एक ही उत्पाद माना है ।
- (ग) प्रकटन विवरण में लागत निर्धारण एवं क्षति रहित कीमत के निर्धारण की दृष्टि से क्लोरीन को सह-उत्पाद/उप उत्पाद मानने के मुद्दे की विधिवत जांच की गई है । प्राधिकारी इस संबंध में प्रकटन विवरण में उल्लिखित स्थिति को बरकरार रखते हैं ।
- (घ) जांच अवधि के संबंध में यह नोट किया गया है कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच अवधि में दो वित्त वर्षों को शामिल किए जाने से रोकता हो । जांच अवधि के संबंध में प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने योग्य केल यह है कि जांच शुरुआत की तारीख की तुलना में जांच अवधि अद्यतन होनी चाहिए । इसे आम तौर पर जांच शुरुआत की तारीख से छह महीने से अधिक पहले का नहीं होना चाहिए ।
- (ङ) याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए समग्र रूप से क्षति का आकलन किया गया है न कि अलग-अलग कंपनीवार ।
- (च) घरेलू उद्योग को क्षति के कारण क्षति विश्लेषण एवं कारणात्मक संबंध के विश्लेषण में दर्शाए गए हैं ।
- (छ) विद्युत की बाजार कीमत के आधार पर क्षति रहित कीमत के परिकलन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के अंतर्गत संगत उपबंधों के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है ।
- (ज) कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों का अनुपात वर्तमान जांच परिणाम के पैरा 8 में दिया गया है ।
- (झ) प्रकटन विवरण के पैरा 52(ii) तथा पैरा 37 के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है । पैरा 52(ii) द्वारा यह सूचित किया जाना आशयित था कि यद्यपि घरेलू

उद्योग की बिक्री कीमत में सापेक्ष रूप से वृद्धि हो रही थी, तथापि यह वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कम थी। अतः उक्त पैरा में उल्लिखित घटी हुई कीमत बढ़ी हुई उत्पादन लागत के तुलनात्मक संदर्भ में है। केवल इस संदर्भ में यह उल्लेख किया गया था कि घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई उत्पादन लागत की तुलना में कम कीमत पर बिक्री करना पड़ रहा था जो पाटित आयातों के कीमत अवमूल्यनकारी प्रभाव को दर्शाता है।

- (ट) बोरे गार्ड के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने स्वयं जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात न किए जाने का दावा किया है। अतः प्राधिकारी द्वारा बोरेगार्ड के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के मामले जिन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है, डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 9.5 में शामिल किए गए हैं। प्राधिकारी केवल उन्हीं कंपनियों को अलग पाटन मार्जिन प्रदान कर सकते हैं जिन्होंने अवधि के दौरान निर्यात किया हो। प्रश्नावली के उत्तर में अपर्याप्तता का प्रश्न केवल तभी होगा जब प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता कंपनी के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना अपेक्षित हो।
- (ठ) प्राधिकारी ने संगत अवधि के लिए क्लोर एल्कली में उल्लिखित माह-वार उच्च एवं निम्न कीमतों पर विचार किया है और सूचित माह-वार कीमतों पर विचार करके जांच अवधि के लिए औसत कीमत अंगीकार की है।
- (ड) प्राधिकारी नोट करते हैं कि नॉर्वे के किसी निर्यातक या नॉर्वे सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि संगत अवधि के दौरान कास्टिक सोडा के लाई रूप का कोई निर्यात नहीं किया गया है। केवल यह दावा कि कास्टिक सोडा के ठोस रूपों की जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया गया है, इस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है।
- (ढ) क्षति रहित कीमत के निर्धारण के संबंध में याचिकाकर्ताओं के बिंदु पर यह नोट किया गया है कि इसका निर्धारण नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
- (ण) वर्तमान जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आयात आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के बाद सही आयात आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस स्रोत के साथ-साथ आई बी आई एस से प्राप्त सौदे-वार आयात आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि डी जी सी आई एंड एस की तुलना में आई बी आई एस ने कुल आयात की अधिक मात्रा सूचित की है। अतः वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने आई बी आई एस पर विश्वास किया है।
- (त) प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आई बी आई एस आंकड़ों की जांच की है और ऐसा प्रतीत होता है कि मूल आई बी आई एस आंकड़ों में कई सौदों में आयात मात्रा को एल एम टी माना गया है और एल एम टी से डी एम टी में बदलने के बाद प्राप्त प्रति इकाई कीमत का उल्लेख किए बिना उसे डी एम टी में बदलने के लिए उसमें अतयधिक कमी की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा ऐसे परिवर्तन/संशोधन के बाद प्रति इकाई कीमत असामान्य रूप से अधिक है अर्थात् चीन, मिस्र, जर्मनी, इंडोनेशिया,

कतर, सऊदी एवं अमेरिका जैसे देशों के मामले में यह लगभग 21,000 रु. से 30,000 रु. के बीच है । संगत अवधि के दौरान विद्यमान कीमत की तुलना में ऐसी कीमतें बहुत अधिक पाई गई हैं । प्राधिकारी अनुभव करते हैं कि केवल चार देशों अर्थात् कोरिया गण., नार्वे, थाइलैंड और ताइवान जहां मूल आंकड़ों के अनुसार प्रति इकाई कीमत असामान्य रूप से कम अर्थात् 6000-8000 रु. के बीच है, जिससे यह सुझाव मिलता है कि इन देशों के सामने दर्शाई गई मात्रा एल एम टी है, के संबंध में मूल आई बी आई एस आंकड़ों में ऐसे सुधार की आवश्यकता है । मौजूदा कीमत/डीएमटी के आधार पर डी एम टी के रूप में मात्रा निकालने के लिए मात्रा से संबंधित मूल आई बी आई एस आंकड़ों के योक्तिकरण के बाद प्राधिकार ने आई बी आई एस आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कुल आयात मात्रा 371157 डी एम टी निकाली है । अतः प्राधिकारी ने उल्लिखित प्रति इकाई कीमत के संदर्भ में डी एम टी के अनुसार आयात मात्रा से संबंधित मूल आई बी आई एस आंकड़ों का योक्तिकरण किया है । भारत में कास्टिक सोडा के कुल आयात के आंकड़ों के संकलन के लिए प्राधिकारी द्वारा इस पद्धति का पालन किया गया है ।

- (थ) दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हुए करार में नकारात्मक जांच परिणाम तथा जांच की शुरुआत की तारीखों और न कि आवेदन की तारीख के बीच 365 दिनों के अंतराल का निर्धारण किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य के साथ-साथ ताइवान से संबंधित वर्तमान जांच की शुरुआत नकारात्मक जांच परिणाम के 365 दिनों के बाद की गई है ।
- (द) कीमत कटौती, कीमत हास के रूप में तथा अन्य विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण इस जांच परिणाम में आगे दिए गए क्षति एवं कारणात्मक संबंध में किया गया है । नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा केव पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता लगाया जाना अपेक्षित है न कि विभिन्न जांचों में संबद्ध देशों से हुई समेकित क्षति का ।
- (ध) लाई और फ्लैक्स संबद्ध उत्पाद के केवल दो रूप हैं और दोनों को ही विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया जाता है । लाई के और प्रसंस्करण द्वारा फ्लैक्स प्राप्त किए जाते हैं ।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

13. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को निर्धारित रूप एवं प्रपत्र में सूचना प्रदान करने की सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी थी । निम्नलिखित कंपनियों से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त हुआ :- :

- i. फार्मोसा प्लास्टिक्स कार्पोरेशन ("एफ पी सी"), ताइवान (उत्पादक)
- ii. ट्राइकॉन एनर्जी लि., अमेरिका (निर्यातक)
- iii. बोरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि., नार्वे

उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित कंपनियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कमियों की सूचना उन्हें दी गई थी। इन कमियों को सही करने के लिए उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी ने फार्मोसा प्लास्टिक्स कार्पोरेशन ("एफ पी सी"), ताइवान (उत्पादक) और ट्राइकॉन एनर्जी लि., अमेरिका (निर्यातक) द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अपूर्ण माना है। दूसरी ओर प्रश्नावली के उत्तर में बोरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि., नार्वे ने यह उल्लेख किया है कि जांच अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी बोरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि. के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करना उचित नहीं समझते हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि एल्केम ए एस जो बोरेगार्ड की सहायक कंपनी है, ने यह उल्लेख करते हुए उत्तर दिया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। अतः प्राधिकारी एल्केम ए 5 के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करना उचित नहीं समझते हैं। इन तथ्यों के आलोक में प्राधिकारी संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करते हैं :-

ड.1 सामान्य मूल्य

थाइलैंड

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड के किसी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर थाइलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। प्राधिकारी क्लोर-अल्कली (हरीमन केमसल्ट द्वारा प्रकाशित) द्वारा सूचित कीमतों को थाइलैंड सहित विभिन्न देशों में घरेलू बाजारों में कास्टिक सोडा की प्रचलित कीमतों का विश्वसनीय संकेतक मानते हैं। तदनुसार प्राधिकारी क्लोर अल्कली द्वारा प्रस्तुत कीमत संबंधी सूचना पर विचार करके थाइलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए *** अम. डॉ./डी एम टी (कारखाना द्वार कीमत) के सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं।

चीनी ताइपेई

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ताइवान के केवल एक उत्पादक/निर्यातक, मै. फार्मोसा प्लास्टिक्स कार्पोरेशन (एफपीसी) (उत्पादक) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इस मामले में निर्यातक मै. ट्राइकॉन एनर्जी लि. ने भी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। तथापि, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य/निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु अपेक्षित महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में इन दोनों से प्राप्त उत्तर को अपर्याप्त पाया है। उन्हें कमियों को दूर करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। तथापि, उक्त उत्पादक/निर्यातक द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः प्राधिकारी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के अंतर को अपूर्ण मानते हैं और अपने पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। प्राधिकारी क्लोर अल्कली (हरीमन केमसल्ट

द्वारा प्रकाशित) द्वारा सूचित कीमतों को, चीनी ताइपेई सहित विभिन्न देशों के घरेलू बाजारों में कास्टिक सोडा की प्रचलित कीमतों का विश्वसनीय संकेतक मानते हैं । तदनुसार प्राधिकारी ने क्लोर अल्कली से प्राप्त कीमत संबंधी सूचना पर विचार करके चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ./डी एम टी (कारखाना द्वार कीमत) के सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं ।

नार्वे

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नार्वे के केवल एक उत्पादक/निर्यातक बॉरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि. ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उसकी सहायक कंपनी, एल्केम ए एस ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में यह कहा है कि जांच अवधि के दौरान कंपनी ने संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया है । अपने उत्तर में बॉरेगार्ड ने यह भी दर्शाया है कि जांच अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया था । अतः प्राधिकारी बॉरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि. और एल्केम ए एस के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना उचित नहीं समझते हैं । इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नार्वे के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्राधिकारी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के अंतर को अपूर्ण मानते हैं और अपने पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं । प्राधिकारी क्लोर अल्कली (हरीमन केमसल्ट द्वारा प्रकाशित) द्वारा सूचित कीमतों को, चीनी ताइपेई सहित विभिन्न देशों के घरेलू बाजारों में कास्टिक सोडा की प्रचलित कीमतों का विश्वसनीय संकेतक मानते हैं । तदनुसार प्राधिकारी ने क्लोर अल्कली से प्राप्त कीमत संबंधी सूचना पर विचार करके चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ./डी एम टी (कारखाना द्वार कीमत) के सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं ।

ड 2. निर्यात कीमत

हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

17. कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय याचिकाकर्ता ने उन सभी बातों जिनके लिए याचिका में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है के लिए कटौती का दावा किया है ।

याचिकाकर्ता के निवेदन

18. याचिकाकर्ता ने अत्यंत परंपरागत अनुमानों को अपनाया है । इस संबंध में वास्तविक सूचना संबद्ध पत्रकारों के पास है । चूंकि याचिकाकर्ता संगत सूचना से अवगत नहीं हैं अतः वे संगत साक्ष्य उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. जहां तक निर्यात कीमत में समायोजनों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने इस संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की है। ट्राईकॉन एनर्जी लि., यू एस ए (निर्यातक) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अपूर्ण पाए जाने पर उसमें दावा किए गए समायोजनों से संबंधित सूचना पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है। इस स्थिति में प्राधिकारी ने समायोजनों पर विचार किया है और उपलब्ध सूचना के आलोक में समुचित समझी गई सीमा तक ऐसे समायोजनों की राशि का अनुमान लगाया है। तदनुसार प्राधिकारी कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत का निम्नानुसार संबद्ध देश-वार निर्धारण करते हैं :

थाइलैंड

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड के किसी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात कीमत का ब्यौरा देते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर थाइलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ. (सी आई एफ)/डी एम टी निर्यात कीमत का निर्धारण करते हैं। प्राधिकारी ने ***% की दर पर पहुंच प्रभारों, ***% की दर पर समुद्री बीमा, *** अम.डॉ./मी.ट. की दर पर समुद्री भाड़े, तथा ***% की दर पर कमीशन में समायोजनों पर विचार किया है। अतः थाइलैंड के सभी निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ./डी एम टी निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है।

चीनी ताइपेई

21. उपर्युक्तानुसार प्राधिकारी ने फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर को अपूर्ण पाया है। अतः फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन को चीनी ताइपेई के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के समरूप ही माना गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीनी ताइपेई के किसी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात कीमत का ब्यौरा देते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ. (सी आई एफ)/डी एम टी निर्यात कीमत का निर्धारण करते हैं। प्राधिकारी ने ***% की दर पर पहुंच प्रभारों, ***% की दर पर समुद्री बीमा, *** अम.डॉ./मी.ट. की दर पर समुद्री भाड़े, तथा ***% की दर पर कमीशन में समायोजनों पर विचार किया है। अतः चीनी ताइपेई के सभी निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ./डी एम टी निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है।

नार्वे

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नार्वे के बॉरेगार्ड इंडस्ट्रीज लि. ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। यह भी नोट किया गया है कि नार्वे के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात कीमत का ब्यौरा देते हुए प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः

प्राधिकारी आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नार्वे के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ. (सी आई एफ)/डी एम टी निर्यात कीमत का निर्धारण करते हैं। प्राधिकारी ने ***% की दर पर पहुंच प्रभारों, ***% की दर पर समुद्री बीमा, *** अम.डॉ./मी.ट. की दर पर समुद्री भाड़े, तथा ***% की दर पर कमीशन में समायोजनों पर विचार किया है। अतः नार्वे के सभी निर्यातकों के लिए *** अम.डॉ./डी एम टी निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है।

ड3. पाटन मार्जिन

23. ऊपर यथानिर्धारित कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्यों तथा निर्यात कीमतों की तुलना करते हुए संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:

(अम. डॉ. /डी एम टी)

क्र. सं.	देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन-रेंज (%)
1	थाईलैंड	कोई उत्पादक/कोई निर्यातक	*****	*****	*****	90-100
2	चीनी ताइपेई	कोई उत्पादक/कोई निर्यातक	*****	*****	*****	60-70
3	नार्वे	कोई उत्पादक/कोई निर्यातक	*****	*****	*****	250-260

च. क्षति

च.1. याचिकाकर्ता के विचार

24. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि:

- संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में कुल आयातों, उत्पादन तथा खपत की तुलना में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- खपत एवं उत्पादन की तुलना में आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है।
- आधारभूत सीमाशुल्क को शामिल करने के पश्चात भारित औसत आयात कीमत, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से काफी नीचे रही है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कीमत कटौती हुई है।

- iv. कीमत कटौती के कारण बाजार में कीमत ह्रास तथा अवमूल्यन दोनों की ही स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जहां उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है वहीं बिक्री कीमतों में गिरावट आई है।
- iv. उत्पादन तथा घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है परंतु क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। उत्पादन एवं घरेलू बिक्री में हुई वृद्धि, मांग में वृद्धि से कम थी। परिणामतः घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- v. विचाराधीन उत्पाद के लिए लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अलावा यद्यपि, वर्ष 2008-09 तक घरेलू उद्योग को लाभ हुआ था तथापि, प्रस्तावित जांच अवधि में उसे वित्तीय घाटा उठाना पड़ा था।
- vi. घरेलू उद्योग तथा घरेलू उत्पादकों दोनों के समग्र बाजार में अत्यधिक गिरावट आई है; जबकि संबद्ध आयातों तथा पाटित आयातों के हिस्से में वास्तविक वृद्धि हुई है।
- vii. घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर कमोबेश स्थिर बना रहा।
- viii. उत्पादन में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- ix. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की ब्याज दर (आर ओ आई) (एन एफ ए के आधार पर) में अत्यधिक गिरावट आई है। नकद लाभ के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। पाटित संबद्ध आयातों के कीमत ह्रास/अवमूल्यन के प्रभाव के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अत्यधिक घाटा हुआ है।
- x. घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

- 25. निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार निवेदन किया है :
- क. नाल्को ने अपनी कुल अपेक्षा के न्यूनतम 25% का आयात किया है क्योंकि घरेलू विनिर्माता कुल अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ नहीं हैं।
- ख. घरेलू बाजार में जी ए सी एल का बाजार हिस्सा लगभग 14.11% है तथा उनके कथनानुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में मंद बिक्री एवं उत्पादन के कारण उसमें गिरावट आई है। जनवरी, 2008 से सितंबर, 2008 की अवधि के लिए कीमतों के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आदर्शतः जांच अवधि से पूर्व की कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए।
- ग. आदित्य बिड़ला समूह द्वारा वर्ष 2009-10 में 23.15% तथा ग्रासिम द्वारा 30.9% आर ओ सी ई दर्ज किया अतः कोई क्षति नहीं हुई।
- घ. आदित्य बिड़ला समूह ने वर्ष 2009-10 के दौरान आई समस्याओं तथा जोखिमों का विवरण दिया जिसमें कच्ची सामग्री में वृद्धि, कोयले की मात्रा

में अत्यधिक कमी तथा कास्टिक सोडा के आयात संबंधी जोखिम आदि शामिल हैं ।

- ड. एस आई ई एल अन्य घरेलू उत्पादकों से पीछे चल रहा है इसके कारण सितंबर, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं ।
- च. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्यवाही जिसमें उत्पादन लागत तथा समुचित लाभ पद्धति में निवेश पर 22% आय प्राप्त हो, स्वैच्छिक है ।
- छ. ताईवान से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के हिस्से में जांच अवधि के दौरान कोई उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है और वह घरेलू उद्योग की कुल बिक्री में 2% से कम है ।
- ज. क्षति अवधि के दौरान मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा स्थिर रहा है और संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति प्रदर्शित नहीं हुई है ।
- झ. क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग स्थिर रहा है और वह आयातों के कारण प्रभावित नहीं हुआ है ।
- ञ. क्षति अवधि के दौरान बिक्री मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है जिससे प्रदर्शित होता है कि उसको कोई क्षति नहीं हुई है ।
- ट. कास्टिक सोडा में कीमत निर्धारण की पद्धतियों को मौके पर कीमतों तथा संपर्क कीमतों के आधार पर बांटा जाता है । लाभप्रदता में गिरावट पाटन के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई है जिन्हें वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया है ।
- ठ. याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी की गई है तथा उसे याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझ कर दबाया गया है ।
- ड. विद्युत की लागत, जो कास्टिक सोडा के उत्पादन की एक प्रमुख लागत है, भारत में बहुत अधिक है तथा घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति आयातों के कारण नहीं बल्कि विद्युत की उच्च लागत के कारण हुई है ।
- ढ. वैश्विक असंतुलन तथा आपूर्ति हेतु घरेलू उद्योग के साथ संभार तंत्र का अभाव; घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण है क्योंकि अधिकांशतः विनिर्माता पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं जबकि एल्युमिनियम उद्योग पूर्वी तट पर अवस्थित है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क परिवहन के माध्यम से कास्टिक सोडा की आपूर्ति हेतु संभार तंत्र लागत अत्यधिक उच्च हो जाती है ।

- ण. कास्टिक सोडा में एन आई पी तथा लाभ के निर्धारण हेतु क्लोरीन को एक संयुक्त उत्पाद माना जाना चाहिए न कि गौण उत्पाद, क्योंकि विश्व भर में इसे संयुक्त उत्पाद ही माना जाता है ।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के संभारतंत्र एवं अवस्थिति की प्रतिकूलता के कारण उच्च भाड़े की स्थिति आयातों पर भी लागू होती है क्योंकि आयातों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी तट पर भेजा जाता है ।
- ख. जहां तक क्षति विश्लेषण एवं एन आई पी में क्लोरीन की कारकता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रखे गए लागत रिकॉर्डों के अनुसार क्लोरीन को गौण उत्पाद/संयुक्त उत्पाद माना गया है । अब तक की गई सभी पूर्ववर्ती जांचों में संबद्ध वस्तुओं के संबंध में प्राधिकारी द्वारा लगातार यही पद्धति अपनाई गई है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में सेस्टेट आदेश के खिलाफ अपील की गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में द्वारा इसको सथगित कर दिया गया है ।
- ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान याचिका घरेलू उद्योग जिसमें गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., डी सी एम श्रीराम कंसॉलिडेटेड लि., एस आई ई एल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स (भवाना शुगर्स लि. की एक इकाई), बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स लि. (जिसे अब आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इंडिया) लि. के नाम से जाना जाता है) शामिल हैं । ये उत्पादक नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उत्पादक हैं । इसके अलावा, इन उत्पादकों का समग्र उत्पादन, भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । इन कंपनियों को भागीदार देश माना गया है ।
- घ. प्रारंभिक जांच के पश्चात सोलारिस केमटेक लि. तथा डी सी डब्ल्यू लि. ने भी क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है । तथापि, मौखिक सुनवाई के समय उपस्थित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच के पश्चात और घरेलू उत्पादकों से प्राप्त अतिरिक्त सूचना जोड़े जाने पर आपत्ति जताई व प्राधिकारी से क्षति आकलन हेतु इस सूचना पर विचार न करने की मांग की । विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने डी सी डब्ल्यू लि. तथा सोलारिस लि. द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार न करने का निर्णय लिया है और हितबद्ध पक्षकारों को भी इसके विषय में सूचित किया है ।
- ड. नियमों के अंतर्गत भागीदार कंपनियां सामूहिक रूप से घरेलू उद्योग हैं । प्राधिकारी ने इन भागीदार कंपनियों के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई क्षति

की जांच की है । क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की इस जांच परिणाम में समुचित स्थानों पर जांच की गई है ।

च.4 क्षति का संचयी आकलन

26. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (iii) में यह उपबंध है कि जब एक से अधिक देश से हुए किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी के लिए केवल उस स्थिति में ऐसे आयातों के संचयी प्रभाव का निर्धारण अपेक्षित होता है जब वह यह निर्धारित करे कि :-

- (i). प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों की 3% से अधिक है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3% से कम है वहां आयातों का संचयी हिस्सा समान वस्तु के आयातों के 7% से अधिक है, और;
- (ii). आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है ।

इस संबंध में निम्नलिखित बातें प्रासंगिक हैं:

- (क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक है;
- (ख) अलग-अलग देशों से हुए आयातों की मात्रा न्यूनतम से अधिक है;
- (ग) प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए थाइलैंड, ताईवान तथा नार्वे से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तुओं पर हुए प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है ।

27. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

28. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

29. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक मापदंडों तथा उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा आदि जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, की जांच निम्नानुसार की गई है।

च 5. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव:

आयात की मात्रा एवं बाजार हिस्सा

30. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (ii) में प्रावधान है कि "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष अत्यधिक वृद्धि हुई है " इस प्रकार, जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने मात्रा के रूप में हुई क्षति के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आई बी आई एस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:-

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	अक्टू'08- दिसं.'09 वार्षिकीकृत
आयात					
संबद्ध देश	मी. ट.	10	3,612	16,941	77,590
समानांतर जांच के अधीन देश	मी. ट.	31725	17357	23463	1,14,565
जांचाधीन पाटित आयात	मी. ट.	31735	20969	40404	1,92,154
अन्य देश	मी. ट.	1,56,593	1,26,053	1,36,037	1,04,771

कुल आयात	मी. ट.	1,88,328	1,47,022	1,76,441	2,96,926
संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	0.01	2.46	9.6	26.13
समानांतर जांच के अधीन देश	%	16.85	11.81	13.3	38.58
जांचाधीन पाटित आयात	%	16.85	14.26	22.9	64.71
अन्य देश	%	83.15	85.74	77.1	35.29
कुल आयात	%	100	100	100	100
घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में संबद्ध पाटित आयातों का हिस्सा	%	0	0.4	1.85	8.32
भारत में खपत की तुलना में संबद्ध पाटित आयातों का हिस्सा	%	0	0.18	0.79	3.44

28. संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद के आयातों में निरपेक्ष मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

वर्ष 2006-07 के दौरान जहां संबद्ध देशों से लगभग कोई आयात नहीं किया गया था, वहीं वर्ष 2007-08 से मात्रा में क्रमशः गिरावट आई और यह जांच अवधि के दौरान अत्यधिक थी । नोट किया जाता है कि मध्यावधि समीक्षा जांच के अंतर्गत आने वाले देशों से हुए आयातों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से हुए आयात यद्यपि उल्लेखनीय थे, तथापि क्षति की अवधि के दौरान उनमें गिरावट देखी गई है ।

29. उत्पाद के आयातों में संबद्ध देशों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो आधार वर्ष के दौरान शून्य के स्तर से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 26% से अधिक हो गया है । अन्य देशों, जिनके संबंध में मध्यावधि समीक्षा की जा रही है, से हुए आयातों में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है । वर्तमान में जांचाधीन देशों से हुए संचयी आयात वर्ष 2006-07 में 16.85% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 64.71% हो गए हैं ।

30. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भी आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।

31. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

च 6. आयातों का कीमत प्रभाव

32. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों से हुए प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का उद्देश्य कीमतों में उल्लेखनीय स्तर तक मंदी लाना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत अवमूल्यन, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) तथा क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से किए गए आयातों की पहुंच लागत से की गई है। निवल बिक्री प्राप्ति की गणना सभी छूटों व करों को घटाकर की गई है। आयातों के पहुंच मूल्य की गणना में संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में 1% प्रहस्तन प्रभार तथा लागू मूल सीमाशुल्क जोड़ दिया गया है। आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की गई और यह पाया गया कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कीमत कटौती हो रही है।

कीमत कटौती

33. यह ज्ञात करने के लिए कि क्या आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कीमत कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की थी। प्राधिकारी ने करों एवं शुल्कों, रिबेटों, छूटों, और कमीशन को छोड़कर बिक्री कीमत पर विचार करके निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण किया है। इस गणना में घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री की समस्त मात्रा शामिल की गई थी। आयातों की पहुंच कीमत का निर्धारण 1% प्रहस्तन प्रभार सहित औसत सी आई एफ आयात कीमत एवं लागू मूल सीमाशुल्क और लागू उपकरण के आधार पर किया गया। तुलना निवल बिक्री प्राप्ति तथा आयातों की पहुंच कीमत के बीच की गई थी। संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम हैं जो पाटित आयातों के कारण हुई अत्यधिक कीमत कटौती का द्योतक है।

(रु./मी.ट.)

क्र.	विवरण	पहुंच कीमत	घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	कीमत कटौती (राशि)	कीमत कटौती-रेंज (%)
1	थाईलैंड	*****	*****	*****	10-20
2	चीनी ताइपेई	*****	*****	*****	20-30
3	नार्वे	*****	*****	*****	30-40
4	संबद्ध देश	*****	*****	*****	20-30

34. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कीमत कटौती हुई है।

कीमत हास

यह निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कीमत हास हुआ है, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारण किया गया कि क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का उद्देश्य कीमत वृद्धि को रोकना था, जो अन्यथा हुई होती। इस प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों की तुलना उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की प्रवृत्ति से की गई।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
1	बिक्री लागत	रु. / मी.ट.	*****	*****	****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	126.72	133.40
2	निवल बिक्री कीमत	रु. / मी.ट.	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96.19	121.12	112.38

35. उपर्युक्त सूचना से यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि बिक्री कीमत में हुई वृद्धि बिक्री की लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। इस प्रकार घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप संबद्ध वस्तुओं की कीमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ है। इस प्रकार जांच अवधि के दौरान कीमत हास हुआ है।

च 7. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

36. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

37. घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों का विवेचन निम्नानुसार है :-

घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	अक्टू'08- दिसं.'09	अक्टू'08- दिसं.'09 वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.ट.	9,49,000	10,05,550	10,62,869	13,73,665	10,98,932
उत्पादन	मी.ट.	8,14,818	9,04,459	9,20,251	11,84,024	9,47,219
क्षमता उपयोग	%	86%	90%	87%	86%	86%
घरेलू बिक्री की मात्रा- याचिकाकर्ता	मी.ट.	7,60,366	8,57,987	8,67,228	11,07,304	8,85,843
घरेलू बिक्री- अन्य घरेलू उत्पादक	मी.ट. 8	10,26,88	10,44,041	10,89,029	13,42,853	10,74,282
कुल आयात	मी.ट.	1,88,328	1,47,022	1,76,441	3,71,157	2,96,926
मांग	मी.ट. 2	19,75,58	20,49,050	21,32,698	28,21,314	22,57,051
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	38.49	41.87	40.66	39.25	39.25

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने क्षमता में विस्तार किया है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लगभग स्थिर रहा है।

लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश से आय

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	अक्टू'08- दिसं.'09
1	लाभ/हानि-लाई	रु. / मी. ट.	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	105	53
2	लाभ/हानि-फ्लैक्स	रु. / मी. ट.	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	133	-31
3	ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपए	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	122	73
4	लाभ/हानि-लाई जमा फ्लैक	रु/लाख	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	124	64
5	नकद लाभ	लाख रुपए	*****	*****	*****	*****

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	135	95
7	नियोजित पूंजी एन एफ ए	लाख रुपए	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	125	118
8	निवेश से आय - एन एफ ए	%	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	98	50

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद का उत्पादन दो रूपों - लाई तथा फ्लेक्स में किया जाता है । दोनों रूपों से संबद्ध लागत और कीमतों में अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने दोनों रूपों के लिए लाभप्रदता का आकलन अलग-अलग किया है । यह नोट किया गया है कि प्रति इकाई उत्पादन पर घरेलू उद्योग के लाभ में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है । इसके परिणामस्वरूप ब्याज कर पूर्व लाभ में भी जांच अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई । लाभप्रदता में गिरावट के परिणामस्वरूप निवेश से हुई आय में, जिसमें वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक वृद्धि हुई थी, जांच अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई ।

40. प्राधिकारी ने उत्पादन और घरेलू बाजार में बिक्री से हुए नकद लाभ पर विचार करके नकद प्रवाह पर पाटन के प्रवाह का निर्धारण किया था । यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान नकद लाभ में भी गिरावट आई ।

41. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी निर्णय लेते हैं कि घरेलू उद्योग का निष्पादन लाभ, निवेश पर आय तथा नकदी प्रवाह के कारण ह्रास हुआ है ।

औसत मालसूची

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2006-07	2007-08	2008-09	अक्टू'08-दिसं.'09 वार्षिकीकृत
1	औसत मालसूची	मी. ट.	2,864	5,341	6,261	10,579
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	186	219	369
	प्रति दिन मालसूची	मी. ट.	7.85	14.63	17.15	28.98

42. उपर्युक्त से यह देखा गया है कि प्रतिदिन की निविष्टियों के साथ-साथ औसत निविष्टियों में जांच अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है ।

रोजगार एवं मजदूरी

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2006-07	2007-08	2008-09	अक्टू'08-दिसं.'09 वार्षिकीकृत
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	2,257	2,064	2,002	1,995
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	89	88
2	मजदूरी	रु./लाख	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	129
3	उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी लागत	रु./मी.ट.	*****	*****	*****	*****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	117	112

43. यह नोट किया गया है कि इस अवधि में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। आगे मजदूरी भुगतान में वृद्धि हुई है जिससे मजदूरी में लगातार सामान्य वृद्धि होने का पता चलता है।

पाटन की मात्रा

44. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति पाटित आयातों की सीमा को सूचित करने वाली पाटन की सीमा यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक है।

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

45. इस मामले में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत प्रभाव को कीमत में कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री प्रभाव जो कि सकारात्मक है में प्रदर्शित किया गया है। आगे पाटित आयातों ने घरेलू बिक्री कीमत को उस सीमा तक कम कर दिया है जिससे घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुपात में बिक्री कीमत वसूली प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।

च 8. क्षति संबंधी मापदंडों पर निष्कर्ष

46. इस प्रकार यह देखा गया है कि :

- संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक रूप में वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि उत्पादन और भारत में खपत के कारण हुई है।
- आयातों से अत्यधिक सीमा तक घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है।
- घरेलू उद्योग उस हालात में कीमतों में कमी करने को बाध्य हुआ है जबकि इसके उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमत में मंदी ला रहे हैं।
- लाभ, निवेश पर आय और घरेलू उद्योग का नकद प्रवाह आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कम हुआ है।

- v. घरेलू उद्योग की निविष्टियों में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है ।
- vi. क्षति के परिमाण के रूप में पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।
- vii. घरेलू उद्योग का उत्पादन आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़ा है और क्षमता उपयोग सामान्यतया स्थिर रहा है ।
- viii. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है ।
- ix. मजदूरी एवं उत्पादन का पाटन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखाई देता है । तथापि, वित्तीय मापदंडों सहित क्षति के अन्य बड़े मानदंडों में कोई गिरावट नहीं आई है ।

47. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण आर्थिक मानदंडों पर वास्तविक क्षति का सामना करना पड़ा है ।

च 9. अन्य ज्ञात क्षति मानदंड और कारणात्मक संबंध

48. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत प्रभाव की मौजूदगी की जांच करने के लिए इसकी कम कीमत पर बिक्री तथा कीमत में कमी और ह्रास के प्रभाव की पाटनरोधी करार और भारतीय नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य निर्देशक सूचित मानदंडों के अनुरूप यह देखने के लिए जांच की गई है कि पाटित आयातों के अलावा क्या अन्य कोई कारक घरेलू उद्योग की क्षति में शामिल तो नहीं हैं, तदनुसार निम्नलिखित मानदंडों की जांच की गई :-

अ. अन्य स्रोतों से आयात की मात्रा एवं कीमत

जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से इतर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात मात्रा के रूप में अत्यधिक है । इसलिए प्राधिकारी ने तीसरे देशों से हुए आयातों की जांच की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यू एस ए, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, चीन एवं इंडोनेशिया से आयात न्यूनतम स्तर से अधिक होने की सूचना है । प्राधिकारी यू एस ए, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया से आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच कर रहे हैं । चीन एवं इंडोनेशिया के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन पर पाटन मार्जिन पहले से ही लागू हैं ।

ii. मांग में संकुचन

संबद्ध वस्तुओं की मांग में संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है और इसलिए घरेलू उद्योग की क्षति के लिए देश में मांग की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है ।

iii. खपत के स्वरूप में परिवर्तन

खपत के आंकड़े उत्पाद के खपत के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करते हैं ।

iv. प्रौद्योगिकी विकास

किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ।

v. व्यापार प्रतिबंधक व्यवहार और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है। घरेलू उद्योग संघटक संबद्ध वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं और वह अधिक घरेलू उत्पादन एवं बिक्री करते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रतिस्पर्धा की शर्तों के कोई साक्ष्य या व्यापार प्रतिबंधक व्यवहार को प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया है।

vi. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री मात्रा घरेलू उद्योग की किसी क्षति के लिए काफी कम है। इसका कारण चाहे कुछ भी हो इससे यह सिद्ध होता है कि जहां तक घरेलू बिक्रियों का संबंध है, घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी आई है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

घरेलू उद्योग की उत्पादकता में प्रति कर्मचारी उत्पादन अथवा प्रतिदिन उत्पादन के रूप में सुधार हुआ है। उत्पादकता में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग की क्षति का कारक नहीं हो सकती है।

49. उपर्युक्त गैर आरोप विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग की क्षति का कोई अन्य कारण नहीं है।

कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

50. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन महत्वपूर्ण आर्थिक मानदंडों पर वास्तविक रूप से विकृतिकारी है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निम्नलिखित आधार पर विश्लेषण किया गया है:

(i) संबद्ध देशों एवं अन्य जांचाधीन देशों से पाटित आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की महत्वपूर्ण रूप से कीमतों में कमी कर रहे हैं। इसी प्रकार घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ कम कीमत पर बिक्री करने पर बाध्य हुआ है। इस प्रकार पाटित आयात से कीमत ह्रास हुआ है।

(iii) लाभ, नकद प्रवाह एवं निवेश पर आय जैसे व्यापक वित्तीय मानदंडों के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन में कीमत में ह्रास के कारण विकृति आई है।

च 10. क्षति मार्जिन :

51. घरेलू उद्योग के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निम्नतर शुल्क नियम, क्षति रहित कीमत को अपनाते हुए क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। देशवार पहुंच मूल्य एवं क्षति मार्जिन का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:

क्षति मार्जिन

देश	उत्पादक	पहुंच कीमत रू./ डीएमटी	पहुंच कीमत रू./ डीएमटी	क्षति मार्जिन रू./ डीएमटी	क्षति मार्जिन अम.डॉ./डी एम टी
थाईलैंड	सभी उत्पादक/निर्यातक	*****	*****	*****	*****
ताइवान (चीनी ताइपेई)	सभी उत्पादक/निर्यातक	*****	*****	*****	*****
नार्वे	सभी उत्पादक/निर्यातक	*****	*****	*****	*****

छ . निष्कर्ष

52. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात दूसरे सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;
- ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- ग. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है ।

ज. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

53. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद की कीमत सतर प्रभावित होगी । तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन व्यवहारों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी ।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; अतः उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

1. सिफारिशें

55 प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित संदर्भ कीमत तथा आयात के समय पहुंच

मूल्य कॉलम 9 में उलिखित मूल्य कम होने की स्थिति में संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है ।

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	281511 281512	कास्टिक सोडा	कास्टिक सोडा लाई तथा कोस्टिक सोडा सॉलिड/ फ्लैक्स	थाइलैंड	थाइलैंड	कोई	कोई	379	डी एम टी	अम.डॉ.
2.	- वही -	- वही -	- वही -	- वही -	थाइलैंड से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	379	डी एम टी	अम.डॉ.
3.	- वही -	- वही -	- वही -	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	थाइलैंड	कोई	कोई	379	डी एम टी	अम.डॉ.
4.	- वही -	- वही -	- वही -	ताइवान (चीनी ताइपेई)	ताइवान (चीनी ताइपेई)	कोई	कोई	361	डी एम टी	अम.डॉ.
5.	- वही -	- वही -	- वही -	ताइवान (चीनी ताइपेई)	चीनी ताइपेई से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	361	डी एम टी	अम.डॉ.
6.	- वही -	- वही -	- वही -	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	ताइवान (चीनी ताइपेई)	कोई	कोई	361	डी एम टी	अम.डॉ.
7.	- वही -	- वही -	- वही -	नार्वे	नार्वे	कोई	कोई	379	डी एम टी	अम.डॉ.
8.	- वही -	- वही -	- वही -	नार्वे	नार्वे से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	379	डी एम टी	अम.डॉ.
9.	- वही -	- वही -	- वही -	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	नार्वे	कोई	कोई	379	डी एम टी	अम.डॉ.

इस अधिसूचना के प्रयोजार्थ "पहुंच मूल्य" का तात्पर्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य से है और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 31, 819 और 9 के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल हैं ।

ट. आगे की प्रक्रिया:

इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2011

FINAL FINDINGS

Sub:- Final Findings of anti-dumping investigation concerning imports of Caustic Soda originating in or exported from Thailand, Chinese Taipei and Norway.

14/1/2010-DGAD – Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

A. Procedure

2. The procedure described below has been followed.

- i The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the Rules, received a written application from Alkali Manufacturer's Association of India (AMAI), Delhi on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Caustic Soda originating in or exported from Thailand, Norway and Taiwan (Chinese Taipei) (hereinafter referred to as subject countries).
- ii Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented.
- iii The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
- iv The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.

- v. The Authority issued a public notice dated 31st May 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- vi. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
- vii. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
- viii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- ix. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
- Chemex Industry Co. Ltd
Phoenix Pulp & Paper Company
Siam Occidental Electrochemical Company
Thai Fermentation Industries
Thai Organic Chemicals Co.
Thai Paper Mills
Thai Plastic & Chemicals Public Co., Ltd.
Thasco Chemical Co., Ltd.
Cathay Chemicals Co. Ltd., 12 Fl Kuang
Borregaard Industries Ltd.
- x. The following exporters/producers/associations/Embassy from Subject countries have responded to initiation notification:
- Formosa Plastics Corporation – Taiwan
Vinythai Public Company Limited, Thailand. Department of Foreign Trade, Thailand
Tricon Energy Limited, US
Borregaard Industries Ltd., Norway
Elkem AS
- xi. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Abhay Chemical Limited
Albright Wilson Chemicals Limited
Arvind Mills Limited
Central Pulp Mills Limited
Deepak Nitrite Limited
Godrej Soaps Limited
Gujarat Narmada Fertilizers & Chemicals Limited
Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited
Indian Farmer Fertilizer Co.Op Limited
Indian Oil Corporation Limited
Jaysynth Dyeschem Limited,
Link Pharma Ltd.
Meghmani Organics Limited
Narmada Chemature Petrochemcials Ltd.
Nirma Limited
Pab Chemicals (P) Limited
Rama News Prints & Papers Limited,
Rubamin Limited
Sabero Organics Ltd.
Torrent Gujarat Biotech Limited
Transpek Silox Industries Limited
National Aluminium Company Ltd
Cynaides and Chemicals Company,
Hitsu Industries Limited
Adani Exports Limited
Libra Foams
Shri Ramachandra Straw Products Limited
Bilag Industries Pvt Ltd.
Daruala Organics Limited
CJ Shah & Co.
Harish Kr & Co.
Hindustan Link & Resin Limited
Hindustan Lever Limited

- xii. In response to the initiation notification, following importers /users/association have responded :

The Dyestuffs Manufacturers' Association of India, Mumbai.
Aluminum Association of India.
Hindalco Industries Limited
Vedant Aluminum Limited

- xiii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

- xiv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered

confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

- xv. Information was sought from the applicant companies. Information relating to injury was provided by two more domestic producers, viz. DCW Ltd. and Solaris Ltd. However, the interested parties present at the time of oral hearing objected to addition of information from more domestic producers after initiation and demanded that the Authority should not consider their information for injury assessment. Considering the objection raised by the opposing interested parties, the Authority decided not to consider the information filed by DCW Ltd. and Solaris Ltd. post-initiation and informed the interested parties about the same.
- xvi. The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;
- xvii. Investigation was carried out for the period starting from 1st Oct., 2008 to 31st Dec., 2009 (POI). The examination of trends, for the purpose of injury analysis covered the period from April 2006–March 2007, April 2007–March 2008 April 2008–March 09, and the POI.
- xviii. The Authority held a public hearing on 24th May, 2011 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the interested parties. The interested parties were asked to file written submissions and rejoinders, if any. The written submissions and rejoinders received from interested parties are considered in the final findings to the extent considered relevant.
- xix. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings was disclosed on 17th June, 2011 and comments received thereon are appropriately addressed in the final findings.
- xx. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1 Submissions of the domestic industry

3. Submissions made by the domestic industry are briefly as follows

- i. The product under consideration in the present application is Caustic Soda.
- ii. All forms of Caustic Soda (Lye and solids) are covered within the scope of the product under consideration.
- iii. These two forms of Caustic Soda are like articles. The issue has been examined by the Authority in various investigations earlier concluded. The issue has been examined by the CESTAT also it has been upheld that these forms of Caustic Soda are like articles.

B.2 Submissions made by other interested parties

4. Caustic Soda in Lye form and Flake form are significantly different in terms of prices. Therefore, analysis of dumping, injury and causal link should be made separately for Lye form and flake form.

B.3 Examination by the Authority

5. The Authority has examined the matter as under:

- i. The Authority notes that Caustic Soda Lye and Caustic Soda Flakes are only two different forms of Caustic Soda. The former is processed further to obtain solid form. The two are essentially same in terms of technical characteristics, manufacturing process, technology, function and use. Mere difference in form of the product does not render them dislike articles. In all the previous investigation, the Authority has considered Lye and solid form of Caustic Soda as one product.
- ii. The product under consideration in the present investigation is sodium hydroxide generally known as caustic soda. Caustic soda is chemically known as NaOH. Caustic soda is a soapy, strongly alkaline odorless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. Caustic soda is produced in two forms – lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form. All forms of caustic soda are subject matter of the investigation.
- iii. Caustic soda is used in the manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn and staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining etc.
- iv. Caustic Soda being is an inorganic chemical and is categorized under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading no. 2815. The classification is however indicative only and is not binding upon the scope of product under consideration.
- v. Caustic Soda is produced from three processes, diaphragm, mercury and membrane. However, the final product from the each process produced contains similar physical and chemical characteristics.

- vi. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD rules provides as under:

"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation".

- vii. The applicant claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.
- viii. The Authority notes that there is no significant difference in subject goods produced by the Indian industry and imported from subject countries. Even though the product is produced through different process, the subject goods produced by the Indian industry and that imported from subject countries are comparable in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the other interested parties has raised any objection in this regard. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as like articles to the subject goods imported from subject countries in accordance with the anti-dumping Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

C.1 **Submissions by the domestic industry**

6. Submissions made by the domestic industry are briefly as follows:-

- i. The petition is filed by Alkali Manufacture Association of India.
- ii. Association in Executive Committee meeting decided to file the present petition for imposition of anti dumping duty. The decision has been taken in accordance to by laws of Association.
- iii. All Indian producers of Caustic Soda are members of the Association.
- iv. Production of participating companies and supporting companies account for a major proportion of total Indian production. The petition therefore satisfies the standing and the petitioner constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

C.2 Submissions by interested parties

7. Submissions by other interested parties are briefly as follows:
- i. Petitioner has been conveniently excluding and including members of the association to take part in the investigation.
 - ii. Selective participation and constitution of Domestic Industry clearly shows lack of transparency and divulging the true affair of the affected industry as a whole.
 - iii. Petitioner should not be allowed to abuse the process of filing repeated and continuous application merely to protect the private business interests.

C.3 Examination by the Authority

8. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:
- i. *"Domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only.*
 - ii. The application was filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI). The application was filed by the association on behalf of the following domestic producers, who provided relevant information.

Gujarat Alkalies & Chemicals Limited
Grasim Industries Limited
DCM Shriram Consolidated Limited
SIEL Industrial Complex
Bihar Caustic & Chemicals Limited
 - iii. Following companies supported the petition filed by AMAI.

Reliance Industries Limited
Kanoria Chemicals & Industries Limited
Gujarat Fluorochemicals Limited
Solaris Chemtech Limited
DCW Limited
Jayshree Chemicals Limited
 - iv. Post initiation, Solaris Chemtech Limited and DCW Limited also provided their injury information. However, the interested parties, during the course of oral hearing, objected to addition of information by the said two domestic producers after initiation and urged the Authority not to consider their information for injury assessment.

Considering the objection raised by the opposing interested parties, the Authority decided not to consider the information filed by DCW Ltd. and Solaris Ltd. and informed the interested parties about the same.

- v. The interested parties have argued that the petitioner has changed composition of domestic industry in every case concerning the subject product. In this regard, the Authority observes that nothing is prescribed in the law to require that the composition of domestic industry in different investigations relating to the same product will be the same. Nor any interested party has established that this has in any way prejudiced the present investigation.
- vi. Authority notes that the companies who have provided their injury data and which have been duly taken on board by the Authority, collectively account for a major proportion (approx. 44%) of total Indian production. The petition, therefore, satisfied the requirements of standing under the Rules. Further, the participating companies constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.

D. OTHER ISSUES

D1. Issues raised by interested parties.

- 9. Some of the other issues raised by the interested parties are as follows:
 - a) Letter of Alkali Manufacturers' Association of India indicated only Thailand as a subject country for initiating the anti dumping Investigation. Therefore, investigation against other countries was inappropriate.
 - b) Finding of Director General Safeguards needs to be considered by DGAD.
 - c) Significant improvement post July 2009.
 - d) Data till March 2010 considered by Director General (Safeguards) and hence, Designated Authority should consider the information and development taken place subsequently.
 - e) Injury analysis: Decline in profitability Q3 of 08-09 was due to Global Recession
 - f) The investigation period is inappropriate as it covered recession in global market.
 - g) Petitioner has overstated imports volume by repeating import transactions. Petition contains information, which has been inflated to the extent of staggering 853.85%.
 - h) While arriving at ex- factory export price, petitioner has claimed deductions for which petitioner has not provided any evidence in the petition.

- i) The petitioner has claimed excessive confidentiality. Even cumulative figures relating to domestic industry as a whole have been claimed confidential.
- j) Current initiation is in contravention of the ministerial declaration dated 14th November, 2001 with regard to back to back investigations. Application for the present initiation was filed on 5th of May, 2011. The present application has been filed within 365 days of the final negative determination with regard to imports from Taiwan of the same period.
- k) Imports from Canada are above de-minimis as per the handouts circulated by the domestic industry during oral hearing. Therefore, exclusion of Canada from the investigation is not proper.

D.2 Submissions by petitioner:

10. The following submissions are made by the petitioner:

- a) Petitioner had already filed errata in this regard. As submitted in the Written Submissions, the petition in its relevant part makes it evident that the petition is in respect of Thailand, Norway and Taiwan.
- b) What the Director General Safeguard stated is that there was no justification for continued imposition of safeguard duty, particularly because anti-dumping duty was in place. The Director General has not stated that the industry no longer suffered material injury and anti-dumping duty is not required to be imposed.
- c) The Final Findings of the Director General are relied upon which clearly establishes that the Director General has not concluded that anti-dumping duty is not required to be imposed.
- d) The argument is factually incorrect in as much as it assumes that the profitability of the domestic industry in Q-3 was low. In fact, profitability of the domestic industry in Q-3 was relatively better as compared to subsequent part of the period of investigation. Table below demonstrates—

S NO	Months/ Quarterly	NSR Lye	NSR Lye	NSR Flake	NSR Flake	NSR Chlorin e	NSR Chlorin e	NSR ECU	NSR ECU	NSR ECU	NSR ECU
		Rs/MT	Index	Rs/MT	Index	Rs/MT	Index	Rs/MT	Index	US\$/M T	Index
1	2006-07	***	100	***	100	***	100	***	100	***	100
2	2007-08	***	94	***	97	***	116	***	97	***	109
3	2008-09	***	118	***	122	***	64	***	109	***	109

4	Oct'08-Dec'09 (POI)	***	112	***	109	***	29	***	99	***	92
5	Oct'08-Dec'08	***	121	***	118	***	6	***	102	***	94
6	Jan'09-March'09	***	131	***	139	***	Neg.	***	106	***	98
7	April'09-June'09	***	122	***	120	***	6	***	103	***	94
8	July'09-Sep'09	***	95	***	90	***	119	***	99	***	92
9	Oct'09-Dec'09	***	93	***	88	***	28	***	82	***	79

- e) The argument is legally and factually untenable. By their own version, it was a problem of "global recession". We are not concerned with "global recession" in the present. It was not a problem of India specific recession. Further, even if global markets suffered in this period, the Indian Market did not suffer from recession. So, as far as Indian producers are concerned, their performance should not have got impacted due to alleged recession.
- f) The issue has already been clarified in previous submissions. The revised import statement has already been filed. Briefly, there were repeated import transactions in the IBIS import data itself on which the petitioner relied while submitting the application.
- g) Petitioner has adopted most conservative estimates. The actual information in this regard is with the parties concerned. Petitioner cannot even provide the relevant evidence, as petitioner is not privy to the relevant information.
- h) The petitioner has disclosed such information as is not commercially sensitive. Information which is commercially sensitive or disclosure of which can significantly impact the business interests of the member companies cannot be disclosed.
- i) There is no such contravention. The current initiation is after 12 months of the previous findings by the authority.
- j) The argument is without basis. Written Submissions are relied upon, wherein the domestic industry has shown that a very significant portion of

imports have taken place in the western region. In fact, there are negligible imports at Eastern customs ports. It is also pointed out that consumption by aluminium industries comprises only ***% of total consumption of caustic soda. The relevant information is reproduced below –

S.No	End Users	Consumption %
1	Pulp & Paper	20.25
2	Alumina	17.92
3	Organics	10.21
4	Inorganics	11.32
5	Soaps & Detergents	7.43
6	Textiles	20.33
7	Water Treatment	1.78
8	Miscellaneous	10.70

D.3 Examination by the Authority:

- As regards DG Safeguards findings the Authority notes that DG Safeguard's findings relate to surge in imports which is different from the ground on which the Designated Authority for anti dumping recommends measures.
- The total production data of the domestic industry available in par 364 of DG Safeguards findings dated 09th April, 2010 have been compared with the same submitted to DGAD and it is found that there are three years which are common in both i.e. year 2006-07, 2007-08 and 2008-09. The Authority finds a slight variation in the production data during these three years which is approximately**% to **%. This variation could be due the fact that the PUC in DG Safeguards investigation was Caustic Soda Lye while the same in the present investigation is both lye and flakes.
- As regards inflated import volumes claimed by the domestic industry, the Authority notes the petitioner has acknowledged the error caused due to repetition of import transactions at the end of the data agency from which the import data was sourced by them.
- The import volume from Canada during POI, as referred to above, has been found below de-minimis vis-à-vis total volume of imports during POI as reported by IBIS which has reported a higher volume of total imports than DGCI&S. The Authority has accepted the IBIS source which has captured a higher volume of total imports compared to DGCI&S when transaction by transaction data is available from both the sources.

D.4 Post Disclosure comments of interested parties:

- The following are the comments of M/S Vedanta Aluminium Limited and other interested parties in response to Disclosure statement:-
 - Vedanta Aluminium Limited has not been taken as interested party as per Disclosure.

- b) Caustic Soda Lye and Flakes are two distinct products and are not like articles, as their products with distinct properties, uses and price.
- c) Chlorine and Caustic Soda are treated co-products worldwide. They should be treated so in India as well so that the respective cost of production as separately computed and common cost upto the point of separation has to be divided on an equitable basis.
- d) Domestic manufacturers in general cannot manage the Chlorine disposal and for this reason cannot run on full capacity.
- e) Economics of Caustic Soda production is linked with economics of Chlorine. Hence, the realization and cost are measured for both products on a composite basis.
- f) POI has been selected covering parts of two financial years so that Domestic industry can manipulate the data.
- g) Documents available in public domain show no injury to domestic industry and in fact they are making huge profit and return on investment. The case of individual Companies which have recorded higher ROCE has been quoted.
- h) Imports have not caused injury to the domestic industry. Rather, imports are caused by shortage of material in India. Imports of Caustic Soda in India are necessitated due to
 - i. Effective limited capacity of DI on account of Chlorine off-take issues.
 - ii. Geographical imbalances in demand and supply
- i) Real cause of injury to Domestic industry in India is high cost of power and not the dumped imports.
- j) For calculation of NIP, market price of power has to be taken as per RIL Vs. Designated Authority – 2006 (202) ELT 23(SC). For costing of Caustic Soda, Chlorine be treated as co-product.
- k) The Authority must state the proportion of production of the applicants in total Indian production. In the present investigation the applicants have a share of less than 50% of total Indian production. Hence, they do not have any standing in the present investigation.
- l) The Authority at one place has noted that domestic industry has reduced prices and other place that the increase in price was less than the increase in cost of sales.
- m) Import data figures have been continuously modified until disclosure statement.
- n) Exclusion of Canada from the investigation renders initiation bad in law.
- o) Exporter have independently called IBIS data and it is noted that Canada still remains above de- minimis and prices from Canada are lower than that of imports From Taiwan.
- p) Designated Authority should specifically disclose the methodology in adopting and compiling the data and notify the transaction entries considered along with quantities and prices.

- q) Reference is made to ministerial conference at fourth session at Doha in November 2001 on implementation issues where it was agreed that no investigation is to be initiated within 365 days of previous negative finding. Sun set review in respect of caustic soda from EU, Indonesia, and Chinese Taipei arrived at a negative finding in respect of Taiwan. Present application is filed within 365 days of the said negative finding.
- r) Designated authority has failed to distinguish exactly how much injury has been caused by the present subject countries and how much is being caused from other countries in parallel investigations. Injury to domestic industry is due to other countries in the parallel investigations.
- s) For determining dumping margin lye and flaks were considered together which is not proper
- t) Selling price of Domestic industry is over NIP.

D.5 Post Disclosure submissions of Royal Norwegian Embassy:

12. The following are submissions of Royal Norwegian Embassy:-

- i. Norwegian Co. Elkem AS has also responded but it is not reflected in Disclosure Statement.
- ii. Annex. 1, Para 4, states incorrectly that there has been no comments filed on Product under Consideration. Norway has stated that "investigation covers Caustic Soda in two distinct forms. Solid is traded under HS Cod 2815.11 and lye under 2815.12.
- iii. It is not appropriate to conclude with regard to Borregaard that there "is no export to India by the company during Period of Investigation" and the "Authority does not consider it appropriate to give individual Dumping Margin to the Co". It is contrary to Anti Dumping Agreement.
- iv. Company did not receive any deficiency notice by the authorities.
- v. There has been no export by both the companies to India and thus there should be no anti dumping investigation against them.
- vi. Norway questions the price information from Chlor Alkali as basis for determination of normal value. The price information reported is without any reference to which of the prices that have been used for calculations by the authority.
- vii. Complainant showed no imports of Caustic Soda in solid form from Norway. It is confirmed by official Norwegian export statistics. Thus, no basis for claiming neither dumping nor injury or causal link for Caustic Soda in solid form and duty to be imposed thereafter.
- viii. Both the companies in their replies have shown that they are not dumping in Indian market or even exporting.

D.6: Post Disclosure comments of the Petitioner:-

13. Following are the comments of petitioner:-

- i. Anti-dumping duty may be imposed only on fixed amount basis.

- ii. Valuation of captive inputs at their market values for determination of non-injurious price (NIP).
- iii. The Authority must consider gross fixed assets or in the alternative consideration of net fixed assets at their present market value for determination of NIP.
- iv. Since foreign producers of non-cooperative, the Authority must proceed with best available information.

D.7 Examination by Authority:

14. The Authority has examined the post-disclosure comments of the interested parties as under:-

- a) The submissions of Vedanta Aluminium Ltd have been duly examined in the present findings.
- b) The Authority notes that Caustic Soda Lye and Caustic Soda Flakes are only two different forms of Caustic Soda. The former is processed further to obtain solid form. The two are essentially same in terms of technical characteristics, manufacturing process, technology, function and use. Mere difference in form of the product does not render them dislike articles. In all the previous investigation, the Authority has considered Lye and solid form of Caustic Soda as one product.
- c) Treatment of Chlorine as a co-product/by-product from the point of view of costing and determination of NIP has been duly examined in the Disclosure statement. The Authority upholds the position already spelt out in this regard in the Disclosure statement.
- d) As regards POI, it is noted that there is no provision under the Rules which bars a POI covering two financial years. The only consideration for the Authority in regard to POI is that POI should be the latest vis-à-vis the date of initiation of investigation, generally not more than six months old vis-à-vis the date of initiation.
- e) Injury has been assessed for the petitioner companies as a whole and not individual company-wise.
- f) The causes of injury to domestic industry have been reflected in the injury analysis and analysis of causal link.
- g) Regarding calculation of NIP on the basis of market price of power, the Authority notes that NIP has been determined in accordance with relevant provision under the Rules.
- h) The proportion of applicant companies in the total Indian production is indicated in para 8 of the present findings.
- i) There is no contradiction between what was stated in para 52 (ii) vis-à-vis para 37 of the Disclosure statement. Para 52(ii) was intended to convey that though the selling price of the domestic industry was increasing in absolute terms, it was lower than the increase in the cost of production. Thus the reduced price referred to in the said para was in a relative context of increased cost of production. In this context only it was stated that the Domestic Industry was forced to sell at reduced prices vis-à-vis the increased cost of production, which reflected the price suppression effect of dumped imports.

- j) As regards Borregaard, the Authority notes that the exporter himself claimed no exports of the subject goods during period of investigation. Therefore, the Authority is not in a position to grant individual dumping margin to Borregaard. Cases of such producers/exporters who have not exported the subject goods during the POI are covered under Article 9.5 of WTO Agreement. The Authority can grant individual dumping margin only to those companies who have exported the product during POI. The question of deficiencies in the questionnaire response would arise only if the Authority is required to determine dumping margin for the responding company.
- k) The Authority has considered the average of the month-wise high and low prices mentioned in the Chlor Alkali for the relevant period and has adopted the average price for the period of investigation by considering month-wise prices reported.
- l) The Authority notes that no exporter from Norway nor the Government of Norway has claimed that no exports of Lye form of Caustic Soda was made during the relevant period. Mere claim that solid forms of Caustic soda were not exported during POI is insufficient for the purpose.
- m) Regarding the petitioner's point relating to determination of NIP, it is noted that the same has been determined on the basis of the relevant provision under the Rules.
- n) For the purpose of present findings, the authority has considered the correct import data after compiling and analyzing the same obtained from different sources. The Authority has examined the transaction wise import data from both DGCI&S source as well as from IBIS. It is noted that IBIS has reported a higher volume of total import than the DGCI&S. Therefore, the Authority has relied upon IBIS source in the present investigation.
- o) The Authority has examined the IBIS data submitted by the exporter and it appears the import volume in original IBIS data, in several transactions, has been treated as LMT and has been substantially reduced in order to convert it into DMT without referring to per unit price obtained after such conversion. The authority notes that per unit price obtained after such conversion /revision by the exporter is abnormally high i.e. approximately in the range of Rs. 21,000 to 30,000 in the case of countries such as China, Egypt, Germany, Indonesia, Qatar, Saudi and USA. Such prices are found to be quite high vis-a-vis the prevailing price during the relevant period. The Authority does feel that there is a need for such revision in original IBIS data only in respect of four countries namely Korea RP, Norway Taiwan, and Thailand where the per unit price as per original data is abnormally low i.e. approximately in range of Rs.6000- Rs. 8000, suggesting that the volume reflected against those countries is in LMT. After rationalization of original IBIS data relating to quantity so as to arrive the volume in terms of DMT on the basis of the prevalent price/DMT, the authority has arrived at the total import volume of 371 157 DMT of the subject goods during POI as per IBIS data. Thus, the authority has rationalized the original IBIS data relating to volume of imports in terms of DMT with reference to per unit price reflected therein. This is the methodology

followed by the authority to compile the figure of total import of caustic soda into India.

- p) The agreement in Doha ministerial conference stipulated a gap of at least 365 days between the negative finding and the date of initiation and not the date of application. The authority notes that the present investigation relating, inter-alia, to Taiwan was initiated after 365 days from the date of negative finding.
- q) Injury to domestic industry in form of price undercutting, price suppression and on various economic parameters caused by the dumped imports from the subject countries is established in injury and causal link analysis dealt later in this finding. Under the Rules, the authority is required only to find injury to the domestic industry resulting from dumped imports and not to segregate injury caused by subject countries in different investigations.
- r) Lye and flakes are only two different forms of the subject goods and both get covered in the product under consideration. Flakes are obtained after processing the lye further.

E. Normal Value, Export Price and Dumping Margin

13. The Authority sent questionnaire to the known exporters from subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Response to the exporters' questionnaire was received from the following companies:

- i. Formosa Plastics Corporation ("FPC") from Taiwan (producer).
- ii. Tricon Energy Limited, USA (exporter)
- iii. Borregaard Industries Ltd., Norway (producer/exporter)

As regards the Companies at (i) & (ii) above, the Authority notes that certain vital deficiencies were pointed out to these companies in respect of the questionnaire response filed by them. A last opportunity was also given to them to make good these deficiencies. However, the same have not been complied with. Therefore, the Authority treats the responses filed by Formosa Plastics Corporation ("FPC") from Taiwan (producer) and Tricon Energy Limited, USA (exporter) as incomplete. On the other hand, Borregaard Industries Limited, Norway, in their questionnaire response, have indicated that there is no export to India by the Company during the POI. Therefore, the Authority does not consider it appropriate to give an individual dumping margin to Borregaard Industries Ltd. Further, The Authority notes that Elkem AS, a sister concern of Borregaard, has responded stating that they have no export of Subject Goods to India during POI. Therefore the Authority does not consider it appropriate to give an individual dumping margin to Elkem AS. In the light of these facts, the Authority proceeds to determine the dumping margin for the producers/exporters of the subject countries as follows:-

E.1 Normal value

Thailand

14. The Authority notes that no producer/exporter from Thailand has submitted the exporters' questionnaire response. Therefore, the Authority

proceeds to determine the normal value for all producers/exporters of Thailand on the basis of best information available. The Authority considers the price reported by Chlor-Alkali (published by Hariman Chemsult) as a reliable indicator of the prevailing prices of caustic soda in the domestic markets in various countries including Thailand. Accordingly, the Authority considers the price information from Chlor-Alkali and determines normal value for all producers/exporters of Thailand at USD *****/DMT (ex factory).

Chinese Taipei

15. The Authority notes that only one producer/exporter namely, M/S Formosa Plastics Corporation ("FPC") (Producer) from Taiwan has submitted exporter's questionnaire response. The exporter in this case, namely M/S Tricon Energy Limited, has also furnished the exporter's questionnaire response. However, the Authority found both these responses to be deficient in respect of vital information requisite for determination of normal value/export price. They were given reasonable opportunity to comply with the deficiencies. However, the requisite information was not submitted by the said producer/exporter. Therefore, the Authority treats their questionnaire responses as incomplete and proceeds to determine the normal value for all producers/exporters of Chinese Taipei on the basis of best information available with it. The Authority considers the price reported by Chlor-Alkali (published by Hariman Chemsult) as a reliable indicator of the prevailing prices of caustic soda in the domestic markets in various countries including Chinese Taipei. Accordingly, the Authority has considered the price information from Chlor-Alkali and determines normal value for all producers/exporters of Chinese Taipei at USD *****/DMT (ex factory).

Norway

16. The Authority notes that only one producer/exporter from Norway, namely, Borregaard Industries Limited has submitted exporter's questionnaire response and its sister concern, namely, Elkem AS has responded stating that the company has no export of Subject goods to India during the POI. In their response, Borregaard has also indicated that there is no export to India by the Company during the POI. Therefore, the Authority does not consider it appropriate to give an individual dumping margin to Borregaard Industries Ltd nor to Elkem AS. Further, the Authority notes that no other producer/exporter from Norway has submitted the exporters' questionnaire response. Therefore, the Authority proceeds to determine the normal value for all producers/exporters of Norway on the basis of best information available. The Authority considers the price reported by Chlor-Alkali (published by Hariman Chemsult) as a reliable indicator of the prevailing prices of caustic soda in the domestic markets in various countries/territories including EU. Accordingly, the Authority has considered the price information from Chlor-Alkali and determines normal value for all producers/exporters of Norway at USD *****/DMT (ex-factory).

E 2. EXPORT PRICE

Submission of interested parties.

17. While arriving at ex- factory export price, petitioner has claimed deductions for which petitioner has not provided any evidence in the petition.

Submission of the petitioner.

18. Petitioner has adopted most conservative estimates. The actual information in this regard is with the parties concerned. Petitioner cannot even provide the relevant evidence, as petitioner is not privy to the relevant information.

Examination by Authority

19. So far as adjustments on export price are concerned, the Authority notes that no exporter from the subject countries has submitted information in this regard. The questionnaire response submitted by Tricon Energy Limited USA(exporter) being found incomplete by the Authority, the information in regard to adjustments claimed therein are not considered by the Authority. In the circumstances, the Authority has taken into account adjustments and estimated the amount of such adjustments as considered reasonable in the light of available information. Accordingly, the Authority determines export price at ex-factory level subject country wise as follows:

Thailand

20. The Authority notes that no producer/exporter from Thailand has submitted questionnaire response giving details of export price. Therefore, the Authority determines the export price for all producers/exporters of Thailand at USD **** (CIF)/DMT on the basis of information provided by the IBIS. The Authority has considered the adjustments on landing charges @ **%, marine insurance @ **%, ocean freight @ USD *** per MT, inland freight @ USD ***per MT and commission @ **%. Thus, net export price is determined as USD ****/DMT for all exporters of Thailand.

Chinese Taipei

21. As aforesaid, the Authority finds the questionnaire response submitted by Formosa Plastic Corporation incomplete. Therefore, Formosa Plastic Corporation has been treated at par with other producers/exporters of Chinese Taipei. The Authority also notes that no other producer/exporter from Chinese Taipei has submitted questionnaire response giving details of export price. Therefore, the Authority determines the export price for all producers/exporters of Chinese Taipei at USD ***** (CIF)/DMT on the basis of information provided by the IBIS. The Authority has considered the adjustments on landing charges @ **%, marine insurance @ **%, ocean freight @ USD *** per MT, inland freight @ USD ***per MT and commission @ **%. Thus, net export price is determined as USD ****/DMT for all exporters of Chinese Taipei..

Norway

22. The Authority notes that Borregard Industries Limited from Norway has responded stating that they have not exported the subject goods to India during the POI. It is also noted that no other producer/exporter from Norway has submitted questionnaire response giving details of export price. Therefore, the Authority determines the export price for all producers/exporters of Norway at USD *** (CIF)/DMT on the basis of information provided by the IBIS. The Authority has considered the adjustments on landing charges @ **%, marine insurance @ **%, ocean freight @ USD *** per MT, inland freight @ USD *** per MT and commission @ 3%. Thus, net export price is determined as USD **** /DMT for all exporters of Norway.

E3. Dumping Margin

23. Comparing the normal values and export prices at ex-factory level as determined above, the dumping margin for the producers/exporters of subject countries is determined as follows:

(US \$ /DMT)						
S No.	Country	Producers/Exporters	Normal Value	Export Price	Dumping margin	Dumping Margin – (%) Range
1	Thailand	Any producer/any exporter	*****	*****	*****	90 -100
2	Chinese Taipei	Any producer/any exporter	*****	*****	*****	60 -70
3	Norway	Any producer/any exporter	*****	*****	*****	250 - 260

F. INJURY**F.1. Views of the petitioner**

24. The domestic industry has submitted that:

- Volume of dumped imports from subject countries have increased significantly. Imports have increased significantly in relation to total imports, production and consumption in India.
- As a result of increase in imports in relation to consumption and production, share of domestic industry has declined.
- Weighted average import price after including basic customs duty have been significantly below the net sales realization of domestic industry, thus causing significant price undercutting.
- Price undercutting has led to both price suppression and depression in the market. Whereas the cost of production have increased, the selling prices have declined.

- iv. Production and domestic sales increased, but capacity utilisation declined. Increase in production and domestic sales was less than increase in demand. Resultantly, market share of the domestic industry declined.
- v. Performance of the domestic industry in terms of profitability for product under consideration has deteriorated over the injury period. Further, whereas the domestic industry had profits till 2008-09, it suffered financial losses in proposed POI
- vi. Market share of the domestic industry and domestic producers as a whole, both, has significantly declined; whereas that of subject imports and dumped imports has materially increased.
- vii. Employment level of the domestic industry remained more or less constant.
- viii. Productivity of the Domestic Industry increased with increase in production.
- ix. ROI (NFA Basis) of the domestic industry has significantly deteriorated over the injury period. Similar is the situation of cash profit as well. The price depression/suppression effect of dumped subject imports has resulted in significant losses to the domestic industry.
- x. Inventory with the domestic industry increased significantly.

F.2. Issues raised by other interested parties and government of subject countries

25. The exporters, importers and other interested parties have submitted as follows:
- a. NALCO had imported a min. of 25% of its total requirement as domestic manufacturers are not able to meet total requirements.
 - b. GACL has about 14.11% of market share in domestic industry and have stated that due to recession sales and production reduced in 2008-09 as compared to 2007-08. Designated Authority should consider the prices before investigation period ideally for period of January 2008 to Sept. 2008
 - c. Aditya Birla in 2009-10 recorded 23.15% ROCE, Grasim Recorded 30.9% in 2009-10 and hence, no injury.
 - d. Aditya Birla stated the problems and risks faced by it during 2009-10 as increase in raw material, substantial reduction in coal quantity and import threat of Caustic Soda.
 - e. SIEL is lagging behind other domestic producers for reasons stated in their annual report for year ending Sept. 2009.
 - f. Any action by Designated Authority to apply 'cost of production plus reasonable profit methodology taking 22% return on investment is arbitrary.
 - g. Share of exports of subject goods from Taiwan does not reflect any substantial increase in Period of Investigation and is below 2% of the total sales of Domestic Industry.
 - h. Domestic Industry's share in demand is stable over injury period and does not show injury due to imports from the subject countries.

- i. Capacity utilization has remained stable over the injury period and has not been affected due to imports.
- j. Sales volume has increased steadily over the injury period showing no injury.
- k. Pricing trends in caustic soda are split on the basis of spot prices and contract prices. Profitability has declined not due to dumping but due to other reasons as stated in annual reports.
- l. Production capacity has been added by the petitioner companies and it has been willfully suppressed by the petitioner.
- m. The cost of power, which is the major cost in production of Caustic Soda, is high in India and any injury to Domestic Industry is not due to imports but due to high cost of power.
- n. Global imbalance and lack of logistics with Domestic Industry for supply is the cause of injury to the domestic industry, as most of the manufacturers are located on west coast, whereas aluminium industry is located on east coast, which leads to high logistics cost for supply of Caustic Soda using road transport.
- o. Chlorine should be considered as a joint product, and not a by-product, in determination of NIP and in the determination of profits in caustic soda as the same is treated so all over the world.

F.3. Examination by the Authority

- a. The Authority notes that higher freight due to logistic and locational disadvantage of domestic industry also applies to the imports a large part of which lands on the Western coast.
- b. As regards factoring in of chlorine in the injury analysis and NIP, the Authority notes that chlorine has been treated as a by-product/joint product as per the cost records maintained by the interested parties. This has been the consistent practice of the Authority in all the previous investigations concerning the subject goods hitherto conducted. The Authority also notes that the CESTAT order in this regard has been appealed against in Hon'ble Supreme Court and the matter has since been stayed by Hon'ble Supreme Court.
- c. The Authority notes that present petition has been filed by Alkali Manufacturing Association of India on behalf of the domestic industry. Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Grasim Industries Limited, DCM Shriram Consolidated Limited, SIEL Industrial Complex (A Unit of Mawana Sugars Limited), Bihar Caustic & Chemicals Limited (now known as Aditya Birla Chemicals (India) Limited). These producers are eligible domestic producers under Rule 2(b). Further, production of these producers collectively account for a major proportion in Indian production. These companies have been considered as participating companies.
- d. Post initiation, Solaris Chemtech Limited and DCW Limited also provided their injury information. However, the interested parties

present at the time of oral hearing objected to addition of information from more domestic producers after initiation and demanded that the Authority should not consider their information for injury assessment. Considering the objection raised by the opposing interested parties, the Authority decided not to consider the information filed by DCW Ltd. and Solaris Ltd. and informed the interested parties about the same.

- e. The participating companies collectively constitute domestic industry under the Rules. The authority has examined injury to the domestic industry with regard to these participating companies. The issues raised by interested parties in relation to injury have been duly examined by the Authority in appropriate places in the findings.

F.4 Cumulative assessment of Injury

26. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules requires that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subject to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such dumped imports, in case it determines that:
 - (i). the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
 - (ii). cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

Following are relevant in this regard:

- (a) The margin of dumping from each of the subject countries is more than the limit prescribed above;
- (b) The volume of imports from individual countries is more than de-minimus.
- (c) The Authority notes that it is appropriate to cumulatively assess the effects of imports of the subject goods from Thailand, Taiwan and Norway on the domestically produced like article, in the light of conditions of competition between the imported article and the like domestic article.

27. Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped

imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

28. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

29. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above such as production, capacity utilization, sales volume, etc. have been examined as under.

F5. Volume Effects of Dumped Imports:

Import Volumes and Market Share

30. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that "while examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India ..." Thus, with regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of volume injury analysis the Authority has relied on import data sourced from IBIS and volume of imports of the subject goods from the subject country have been analyzed as under

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	Oct'08- Dec'09 Annualised
Imports					
Subject Countries	MT	10	3,612	16,941	77,590
Countries under parallel dumping investigations	MT	31725	17357	23463	1,14,565
Dumped imports under investigations	MT	31735	20969	40404	1,92,154

Other Countries	MT	1,56,593	1,26,053	1,36,037	1,04,771
Total Imports	MT	1,88,328	1,47,022	1,76,441	2,96,926
Market Share of subject Imports					
Subject Countries	%	0.01	2.46	9.6	26.13
Countries under parallel dumping investigations	%	16.85	11.81	13.3	38.58
Dumped imports under investigations	%	16.85	14.26	22.9	64.71
Other Countries	%	83.15	85.74	77.1	35.29
Total Imports	%	100	100	100	100
Share of subject dumped imports in relating to production of domestic industry	%	0	0.4	1.85	8.32
Share of subject dumped imports in relating to consumption in India	%	0	0.18	0.79	3.44

28. Imports of the subject product from subject countries have increased significantly in absolute volumes. While there were practically no imports from subject countries in 2006-07, volume gradually increased from 2007-08 and were quite significant in period of investigation. It is noted that imports from other countries separately under midterm review investigation have also increased significantly. It is also noted that imports from third countries, though significant, have declined over the injury period.
29. Share of subject countries in imports of the product has increased significantly from negligible level in base year to over 26% in period of investigation. Imports from other countries for which midterm review is being conducted have also increased over the injury period. The cumulative imports from countries at present under investigation have increased from 16.85% in 2006-07 to 64.71% in period of investigation.
30. Imports of subject goods from subject countries in relation to production as well as consumption in India have also increased during the POI compared to the base year.
31. On the basis of the above, the authority concludes that imports of the product have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

F6. Price effect of imports

32. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries. The net sales realization was arrived after deducting all rebates and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and it was found that the dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry.

Price undercutting

33. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. Authority has determined net sales realization considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts & commissions. Entire sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty and applicable cess. The comparison was done between net sales realization and landed price of imports. The Authority notes that the landed prices of the subject goods are significantly below the selling price of the domestic industry which suggests significant price undercutting being caused by the dumped imports.

(Rs./MT)

SN	Particular	Landed price	Net Selling price of DI	Price Undercutting (amount)	Price Undercutting (%)Range
1	Thailand	*****	*****	*****	10 - 20
2	Chinese Taipei	*****	*****	*****	20 - 30
3	Norway	*****	*****	*****	30 - 40
4	Subject Countries	*****	*****	*****	20 - 30

34. It is seen that the landed price of imports of the subject goods are significantly below the selling prices of the domestic industry, resulting in significant price undercutting.

Price suppression

In order to determine whether the dumped imports are suppressing the domestic prices, the Authority determined whether the effect of such imports is to prevent price increases, which otherwise would have occurred. For the purpose, the import prices of subject goods have been compared with the trends in cost of production and selling price of the domestic industry.

SN	Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI
1	Cost of Sales	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	97	126.72	133.40
2	Net Selling price	Rs./MT	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	96.19	121.12	112.38

35. From the above, it is noted that there is an increase in both the cost of sales as well as the selling price of the domestic industry during POI. However, the increase in selling price is proportionately lower than the increase in the cost of sales. Thus the domestic Industry has not been able to realize prices of the subject goods commensurate with the increase in the cost of production. Thus, price suppression has taken place during the POI.

F7. Economic parameters of the domestic industry

36. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

37. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, capacity utilization and Market share of the Domestic Industry

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	Oct'08-Dec'09	Oct'08-Dec'09 Annualised
Capacity	MT	9,49,000	10,05,550	10,62,869	13,73,665	10,98,932
Production	MT	8,14,818	9,04,459	9,20,251	11,84,024	9,47,219

Capacity Utilization	%	86%	90%	87%	86%	86%
Domestic Sales Volume – Petitioner	MT	7,60,366	8,57,987	8,67,228	11,07,304	8,85,843
Domestic Sales- Other Domestic producers	MT	10,26,888	10,44,041	10,89,029	13,42,853	10,74,282
Total import	MT	1,88,328	1,47,022	1,76,441	3,71,157	2,96,926
Demand	MT	19,75,582	20,49,050	21,32,698	28,21,314	22,57,051
Market share of domestic industry	%	38.49	41.87	40.66	39.25	39.25

38. The authority notes that the domestic industry has added capacity over the injury period. Production of the domestic industry has shown increase over the period. Capacity utilization has remained stable during the injury period. Sales of the domestic industry in the domestic market show continued increase. The market share of the domestic industry has remained more or less stable during the injury period.

Profit/Loss, cash profit and return on investment

SN	Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	Oct'08-Dec'09
1	Profit/loss – lye	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	94	105	53
2	Profit/loss – flakes	Rs/MT	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	108	133	-31
3	Profit before interest	Rs.Lacs	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	105	122	73
4	Profit/Loss – Lye plus Flake	Rs/Lakh	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	107	124	64
5	Cash Profit	Rs.Lacs	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	110	135	95
7	Capital employed NFA	Rs.Lacs	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	99	125	118

8	Return on investments – NFA	%	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	106	98	50

39. The authority notes that the product is produced in two forms – lye and solid. In view of significant difference in the associated cost and price of the two forms, the authority has assessed profitability of the two forms separately. It is noted that profits of the domestic industry per unit of production is significantly reduced during the POI compared to the base year. As a result profits before interest tax also dropped significantly in period of investigation. As a result of decline in profitability, return on investment, which was improving between 2006-07 to 2008-09, dropped significantly in the period of investigation.

40. The authority has determined impact of dumping on the cash flow by considering cash profits generated from production and sales in the domestic market. It is noted that cash profits also declined in the period of investigation.

41. On the basis of the above, the authority concludes that the performance of the domestic industry deteriorated on account of profits, return on investment and cash flows.

Average Inventory

SN	Particulars	UOM	2006-07	2007-08	2008-09	Oct'08-Dec'09 Annualized
1	Average Inventory	MT.	2,864	5,341	6,261	10,579
	Trends	Indexed	100	186	219	369
	Inventory per day	MT	7.85	14.63	17.15	28.98

42. From the above it is seen that both average inventory as well as inventory per day have drastically increased during the POI.

Employment and wages

SN	Particulars	UOM	2006-07	2007-08	2008-09	Oct'08-Dec'09 Annualized
1	Number of Employee	Nos.	2,257	2,064	2,002	1,995
	Trends	Indexed	100	91	89	88
2	Wages	Rs./Lacs	*****	*****	*****	*****
	Trend	Indexed	100	106	132	129
3	Wage cost per unit of production	Rs./MT	*****	*****	*****	*****

	Trend	Indexed	100	95	117	112
--	-------	---------	-----	----	-----	-----

43. It is noted that the numbers of employees declined over the period. Further, wages paid have increased which appears consistent with the normal increase in wages.

Magnitude of Dumping

44. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined for the subject countries are significant.

Factors affecting prices

45. In this case price effects of dumped imports from subject countries are reflected in the price undercutting and price underselling effects which are found to be positive. Further, the dumped imports have suppressed the domestic selling price in as much as the domestic industry has not been able to realize selling prices commensurate with increase in the cost of sales.

F8. Conclusion on injury parameters

46. It is thus seen that:

- i. Imports from subject countries have increased in absolute terms. The increase in imports is significant. Imports have increased in relation to production and consumption in India.
- ii. Imports are undercutting the prices of domestic industry to a significant extent.
- iii. Domestic industry has been forced to reduce the prices in a situation where its cost of production has increased. The imports are thus suppressing the domestic industry's prices.
- iv. Profits, return on investment and cash profits of the domestic industry declined in POI compared to the base year.
- v. Inventories with the domestic industry have increased substantially.
- vi. Dumping margins as a parameter of injury are quite significant.
- vii. Production of the domestic industry increased during POI compared to the base year and the capacity utilization has remained more or less stable.
- viii. Domestic sales increased over the injury period.
- ix. Wages and productivity does not show adverse impact of dumping. However, deterioration has taken place on other vital parameters of injury including the financial parameters.

47. In view of above, Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury on vital economic parameters.

F9. Other Known Injury factors and Causal Link

48. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti Dumping have been examined to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:-

i. Volume and prices of imports from other sources

During POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country have been significant in volume. The Authority therefore examined imports from third countries. The Authority notes that imports beyond de-minimis levels have been reported from USA, Saudi Arabia, South Korea, China and Indonesia. The Authority is conducting midterm review investigation in respect of imports from USA, Saudi Arabia, South Korea. As regards China & Indonesia, the Authority notes that anti dumping duties are already in place.

ii. Contraction in demand

Demand for the subject goods has shown positive growth during the entire injury investigation period and therefore, the injury to the domestic industry cannot be attributed to the lack of demand in the country.

iii. Change in pattern of consumption

The data on consumption does not show any significant change in the pattern of consumption of the product.

iv. Developments in technology

There is no evidence of significant changes in technology submitted by any interested party, which could have caused injury to the domestic industry.

v. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The subject goods are freely importable. The domestic industry constituents are major producers of the subject goods and account for significant domestic production and sales. No other evidence of conditions of competition or trade restrictive practices has been brought to the attention of the Authority by any interested party.

vi. Export performance of the domestic industry

The export sales of the domestic industry is too insignificant in volume to cause any injury to the domestic industry. In any case, it is established that

the domestic industry's performance has deteriorated on the domestic sales.

Productivity of the Domestic Industry

Productivity of the domestic industry in terms of production per employee or production per day has improved. Possible decline in productivity cannot be a factor causing injury to the domestic industry.

49. The above non-attribution analysis shows that no other known factors appear to have caused injury to the domestic industry

Factors establishing causal link

50. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated on vital economic parameters. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is analysed on the following grounds:

- (i) The volume of dumped import from the subject countries and other countries under investigation increased significantly.
- (ii) The subject imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry. Consequently, the domestic industry has been forced to sell at reduced prices vis-à-vis the increased cost of production. The dumped imports, thus, has caused price suppression.
- (iii) Performance of the domestic industry with regard to vital financial parameters such as profits, cash flow and return on investments deteriorated as a result of price suppression.

F10. Injury Margin :

51. Following the lesser duty rule, the non-injurious price determined by the Authority for the domestic industry has been compared with the landed value of imports for determination of injury margin. The country-wise landed value and injury margin is determined as under:

INJURY MARGIN

Country	Producer	NIP Rs./DMT	Landed Price Rs./DMT	Injury Margin Rs./DMT	Injury Margin US\$/DMT
Thailand	All producers/ exporters	*****	*****	*****	*****
Taiwan (Chinese Taipei)	All producers/ exporters	*****	*****	*****	*****
Norway	All producers/	*****	*****	*****	*****

	exporters				
--	-----------	--	--	--	--

G. Conclusions

52. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a. The subject goods have been exported to India from the subject countries below its normal value;
- b. The domestic industry has suffered material injury;
- c. The injury has been caused by the dumped imports from subject countries.

H. Indian Industry's Interest & Other Issues

53. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

54. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

I. Recommendation

55 Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the definitive anti-dumping duty as the difference between the reference price indicated in Col.9 of the table below and the landed value of the subject goods, in case the landed value at the time of importation is below the value indicated at Col.9, is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government:

S. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	281511 281512	Caustic soda	Caustic Soda Lye & Caustic Soda Solid/ Flakes	Thailand	Thailand	Any	Any	379	DMT	USD
2.	- do -	- do -	- do -	- do -	Any Country other than Thailand	Any	Any	379	DMT	USD
3.	- do -	- do -	- do -	Any country other than subject countries	Thailand	Any	Any	379	DMT	USD
4.	- do -	- do -	- do -	Taiwan (Chinese Taipei)	Taiwan (Chinese Taipei)	Any	Any	361	DMT	USD
5.	- do -	- do -	- do -	Taiwan (Chinese Taipei)	Any country other than Chinese Taipei	Any	Any	361	DMT	USD
6.	- do -	- do -	- do -	Any country other than subject countries	Taiwan (Chinese Taipei)	Any	Any	361	DMT	USD
7.	- do -	- do -	- do -	Norway	Norway	Any	Any	379	DMT	USD
8.	- do -	- do -	- do -	Norway	Any country other than Norway	Any	Any	379	DMT	USD
9.	- do -	- do -	- do -	Any country other than subject countries	Norway	Any	Any	379	DMT	USD

For the purpose of this notification, "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

J. Further Procedure:

An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority